

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण गुरुवार 17 सितंबर 2026 वर्ष-9,अंक-226 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com



www.facebook.com/krantisamay1



www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम



राम मंदिर निर्माण का कार्य हुआ पूर्ण, अब रामकथा संग्रहालय का होगा निर्माण

अयोध्या ।

श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद अब निर्माण से जुड़ी एजेंसियों के अंतिम भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अंतिम भुगतान से पहले निर्माण से जुड़ी कंपनियों के बिलों का ऑडिट कराया जाएगा। साथ ही निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अनुबंध की शर्तों के अनुसार कंपनियों को परफॉर्मंस बैंक गारंटी भी देनी होगी। इसके साथ ही अब अंतरराष्ट्रीय श्रीरामकथा संग्रहालय के निर्माण के लिए 10 अक्टूबर से टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में निर्माण कार्य के साथ-साथ विभिन्न चरणों में कंपनियों को भुगतान किया जाता रहा है। अब अंतिम भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने पर अनुबंध की शर्तों के तहत परफॉर्मंस बैंक गारंटी ली जाएगी, ताकि भविष्य में भी निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने बताया कि पारदर्शिता के लिए अंतिम बिलों का स्वतंत्र संस्था से ऑडिट कराया जा रहा है। कीएमसी के रूप में टाटा के अलावा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को करीब 60 से 70 प्रतिशत अंतिम बिलों के ऑडिट की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए दो महीने का समय तय किया गया है। परिसर के बाहर निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के कार्य में करीब तीन से चार महीने का विलंब हुआ है। इसके जनवरी-फरवरी तक पूरा होने की उम्मीद है। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि अब भवन निर्माण समिति का प्रमुख ध्यान अंतरराष्ट्रीय श्रीरामकथा संग्रहालय पर है। संग्रहालय में प्रस्तावित 20 गैलरियों की स्टोरी लाइन अंतिम रूप ले चुकी है। प्रत्येक गैलरी का विषय निर्धारित कर लिया गया है। गैलरियों के निर्माण के लिए 10 अक्टूबर से टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। टेंडर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कार्य शामिल होंगे। इनमें इमर्सिव टेक्नोलॉजी, थ्री-डी और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। अक्टूबर के अंत तक टेंडर फाइनल होने की उम्मीद है। छह माह में गैलरियों बनने की संभावना है।

मोदी सरकार का फैसला- ईपीएफ वेतन सीमा 15,000 से बढ़कर 25,000 रुपये

-51 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

नई दिल्ली ।

केंद्र की मोदी सरकार ने विश्वकर्मा जयंती के मौके पर देश भर के औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। इस निर्णय से देश के लाखों कर्मचारियों को संगठित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा पीएफ नियमों के तहत वेतन की सीमा 15,000 रुपये थी, जो कि आखिरी बार सितंबर 2014 में संशोधित किया गया था। नई सीमा के लागू होने से करीब 51 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।जिनकी मासिक आय 15,000 से 25,000 रुपये के दायरे में आती है। केंद्र सरकार का अनुमान है कि इस विस्तार पर प्रति वर्ष लगभग 11,339 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा, जबकि अर्धराई पांच वर्षों में यह आंकड़ा करीब 56,696 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर को बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। यह मांग लंबे समय से की जा रही थी और इस पर विभिन्न मंत्रालयों के बीच विस्तृत चर्चा हुई, जिसके बाद व्यय वित्त समिति ने इसकी सिफारिश की थी। वेतन सीमा बढ़ने से कर्मचारियों को तीन प्रमुख लाभ मिलने हैं। पहला, उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियमित बचत का लाभ मिलेगा। दूसरा, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के माध्यम से सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन सुरक्षा सुनिश्चित होगी। और तीसरा, कर्मचारी जमा-संबद्ध बीमा योजना (ईडीएलआई) के तहत उन्हें बीमा सुरक्षा भी उपलब्ध होगी। यह कदम पेंशन योग्य वेतन और वैधानिक अंशदान व्यवस्था को वर्तमान वेतन स्तरों के अधिक अनुकूल बनाएगा। केंद्र सरकार का मानना ​​है कि औपचारिक रोजगार केवल वेतन तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके साथ सुनिश्चित और पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा भी जुड़ी होनी चाहिए। यह नई व्यवस्था इसी सिद्धांत को और मजबूत करती है। यह फैसला केवल कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि निियोत्काओं के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा।

कोलकाता में जमीन हड़पने के आरोप में अमित गांगुली गिरफ्तार

कोलकाता ।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता में जमीन हड़पने और भूमि रिकॉर्ड में जालसाजी से जुड़े धनशोधन मामले में अमित गांगुली को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि गांगुली को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया। गांगुली पर फर्जी बोर्ड प्रस्तावों, जाली हस्ताक्षरों वाले बिजली समझौतों और जाली दस्तावेजों के माध्यम से विभिन्न लोगों और संस्थाओं की संपत्तियों पर अवैध रूप से नियंत्रण करने का आरोप है। आरोप है कि वह भूमि रिकॉर्ड में हेरफेर करता था।

नई दिल्ली ।

दो हजार रूपए से अधिक के कमर्शियल यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में सरकार की संबंधित अधिसूचना और हाल ही में जारी एमडीआर फ़ेमवर्क को रद्द करने की मांग की गई है। वकील अंजन दत्ता द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने पर्याप्त कानूनी आधार और व्यापक

जनहित पर विचार किए बिना यह निर्णय लिया है। याचिकाकर्ता ने 14 दिसंबर को जारी अधिसूचना और 15 सितंबर को लागू किए गए एमडीआर फ़ेमवर्क को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त करने की मांग की है। याचिका में तर्क दिया गया है कि यूपीआई को देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और लोगों को कम लागत वाली भुगतान सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। ऐसे में इस पर अतिरिक्त शुल्क लगाना

डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने की नीति के विपरीत है। इस बीच, 2000 से अधिक के कुछ मचेंट यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लागू किए जाने को लेकर राजनीतिक दलों के बीच भी बहस तेज हो गई है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था दुनिया भर में मिसाल बन चुकी है। उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और आम लोगों तक डिजिटल भुगतान की पहुंच

भारत की बड़ी उपलब्धि है। ठाकुर ने कहा, भारत के डिजिटल ट्रांजेक्शन मॉडल की दुनिया भर में चर्चा होती है। बड़े देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भारत आकर देखते हैं कि कैसे चाय बेचने वाला, सड़क किनारे का विक्रेता और छोटे व्यापारी आसानी से डिजिटल भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर इस मुद्दे को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरी रिपोर्ट का गंभीरता से अध्ययन किया जाना चाहिए। अनुराग ठाकुर



ने यह भी कहा कि 2000 तक के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं है और 2000 से अधिक के अधिकांश लेनदेन भी शुल्क के दायरे से बाहर रहेंगे।

वहीं, कांग्रेस समेत विपक्ष ने

वंदे मातरम पर प्रियांक खड़गे की बीजेपी को चुनौती..बिना कागज के गाकर दिखाएं

बेंगलुरु ।

कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने भाजपा नेताओं बीवाई विजयेंद्र और आर. अशोक को चुनौती दी है कि वे बिना टेलीप्रॉम्प्टर या कागज को देख बिना वंदे मातरम के सभी अंतरे गाकर दिखाएं। खड़गे ने कहा कि यदि वे ऐसा करते हैं, तब वे अपने पद से इस्तीफा दे देने वाले हैं। यह चुनौती कर्नाटक सरकार के उस आदेश के बाद आई है, जिसमें सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल शुरुआती दो अंतरे गाने को अनिवार्य किया है, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल की मौजूदगी वाले कार्यक्रमों को इससे बाहर रखा गया है। इसके विपरीत, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 9 जुलाई



को राष्ट्रागन जन-गण-मन के साथ वंदे मातरम के सभी छह अंतरे गाने का निर्देश दिया था। कांग्रेस वर्किंग कमिटी ने 19 अगस्त को अपने 1937 के प्रस्ताव का पालन कर पार्टी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के केवल दो पैराग्राफ गाने का फैसला किया है। यह निर्णय 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गायन पर हुए विवाद और भाजपा के उन आरोपों के बाद लिया गया, जिसमें भाजपा ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत का अपमान करने का आरोप लगाया था।

टीएमसी रैली अनुमति पर कलकत्ता हाईकोर्ट में आज सुनवाई

कोलकाता ।

कोलकाता हाईकोर्ट 17 सितंबर को महत्वपूर्ण पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगा। यह याचिका पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर की गई है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस को हुगली जिले के श्रीरामपुर में निजी जमीन पर जनसभा आयोजित करने की अदालत की पिछली मंजूरी को चुनौती दी गई है। यह जनसभा मूल रूप से 11 सितंबर को होनी थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी। राज्य की सुवेंदु सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वदल भट्टाचार्य ने अदालत को सूचित किया कि मुख्य न्यायाधीश रवींद्र विष्टराराव घुगे की अध्यक्षता वाली

खंडपीठ की अनुमति से यह पुनर्विचार याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति सीगत भट्टाचार्य ने घोषणा की है कि पुनर्विचार याचिका पर 17 सितंबर को सुनवाई होगी। सुवेंदु सरकार और निजी जमीन के मालिक ने खंडपीठ के समक्ष यह प्रश्न उठाया है कि क्या जगन्नाथ ज्यू ट्रस्टी बोर्ड की जमीन पर कोई राजनीतिक रैली, आंदोलन या बैठक आयोजित की जा सकती है। इस मामले में, एक एकल पीठ ने श्रीरामपुर में भीड़-भाड़ वाले जीटी रोड के बजाय उसी निजी जमीन पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जनसभा आयोजित करने की अनुमति दी थी।



उभरती तकनीकों और बहु-डोमेन युद्ध (मल्टी-डोमेन वॉरफेयर) पर अपने अनुभव साझा करने वाले हैं। बहु-डोमेन युद्ध का अर्थ है कि आधुनिक सैन्य अभियानों में जमीन, हवा, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी क्षमताओं को आपस में जोड़कर इस्तेमाल करना। इस बार के

अभ्यास में अमेरिकी सेना की थर्ड मल्टी-डोमेन टास्क फोर्स भी शामिल है, जो लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाले सिस्टम्स और आधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को अभ्यास के ढांचे में एकीकृत कर रही है, जिससे दोनों सेनाओं की संयुक्त युद्धक क्षमता और बढ़ सके।

नेपाल में तीन घंटे के भीतर दो बार भूकंप, मुगु में 4.5 और 4.2 तीव्रता के झटके

- उत्तर-पश्चिमी नेपाल में आधी रात के बाद महसूस हुए भूकंप के झटके, मुगु के साथ दोल्पा और जुमला में भी असर; फिलहाल नुकसान की सूचना नहीं

काठमांडू ।	
उत्तर-पश्चिमी नेपाल में बुधवार तड़के लगातार दो बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीन घंटे के भीतर आए इन दोनों भूकंपों के कारण स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि, शुरुआती जानकारी के अनुसार किसी के हताहत होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की सूचना नहीं है।	
राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केंद्र के अनुसार पहला भूकंप रात 1 बजकर 51 मिनट पर दर्ज किया गया। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.5 रही। भूकंप का केंद्र मुगु जिले के कलाई क्षेत्र के आसपास बताया गया।	इसके करीब ढाई घंटे बाद सुबह 4 बजकर 28 मिनट पर दूसरी बार धरती कांपी। इस भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई। इसका केंद्र भी मुगु जिले के आसपास ही बताया गया। दोनों झटके पड़ोसी जिलों खोल्पा और जुमला के कुछ इलाकों में भी महसूस किए गए।
	नेपाल भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है और यहां समय-समय पर भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। संभावित आपत्तराशोक और किसी तरह के ढांचागत नुकसान की जानकारी जुटाई जा रही है।



फिलहाल दोनों भूकंपों के बाद किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है। अधिकारियों ने स्थानीय स्तर पर स्थिति पर निगरानी जारी रखी है। लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने और भूकंप के दौरान सुरक्षा संबंधी सावधानियां बरतने की अपील की

गई है। नेपाल में हाल के दिनों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी चिंता का माहौल बना हुआ है। ऐसे में तड़के आए दो भूकंपों ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी। हालांकि, वर्तमान स्थिति में किसी बड़ी क्षति की पुष्टि नहीं हुई है।

पीएम मोदी ने केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर बप्पा के दर्शन किए

गृह मंत्री अमित शाह ने भी टेका मत्था

नई दिल्ली ।

गणपति उत्सव के पावन अवसर पर देश के बड़े राजनेताओं ने श्रद्धा और उल्लास के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश के दर्शन किए और देशवासियों के लिए सुख-समृद्धि की कामना की। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नई दिल्ली स्थित आवास पहुंचे, जहां उन्होंने गणपति बप्पा के दर्शन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और आरती उतारी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी पारंपरिक वेशभूषा में नजर

आए। उन्होंने धोती-कुर्ता और सिर पर महाराष्ट्र की पारंपरिक टोपी धारण कर रखी थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर इस विशेष क्षण की तस्वीरें साझा करते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और कामना की कि भगवान श्री गणेश सभी पर अपनी कृपा बणाएं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री के अपने आवास पर आने पर आभार व्यक्त किया और इसे अपने परिवार के लिए सौभाग्य बताया। इसके अलावा, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी पीयूष गोयल के आवास पर पहुंचकर गणपति बप्पा के दर्शन किए और शांति व समृद्धि की प्रार्थना की। दूसरी ओर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई पहुंचकर गणेश



उत्सव में हिस्सा लिया। उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध लालबागवा राजा के दर्शन किए और पूजा-अर्चना कर देशवासियों के कल्याण का आशीर्वाद मांगा। इसके पश्चात, गृह मंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर भी गए, जहां उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ बप्पा के दर्शन

भारत-अमेरिका का युद्धभ्यास 2026 शुरू-

नई दिल्ली ।

भारत और अमेरिका ने अपने वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धभ्यास 2026 का 22वां संस्करण शुरू किया है। उत्तराखंड के ओली और राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा अभ्यास पहाड़ी और अर्ध-पहाड़ी इलाकों में युद्ध की तैयारियों, ड्रोन व स्वायत्त प्रणालियों के उपयोग और एकीकृत युद्ध समूहों (आईबीजी) को मजबूत करने पर केंद्रित है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और संयुक्त परिचालन क्षमता को बढ़ाना है। अभ्यास का उद्घाटन समारोह

हाल ही में उत्तराखंड के ओली फरिन ट्रेनिंग नोड में हुआ, जिसमें भारतीय सेना की 14 इन्फैंट्री डिवीजन के मेजर जनरल अमरीश गुंजन और अमेरिकी सेना की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन के फर्स्ट इन्फैंट्री ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के कमांडर कर्नल बेंजामिन जैकमन ने दोनों देशों के सैन्यकर्मियों को संबोधित किया। इस संयुक्त अभ्यास में भारत और अमेरिका के करीब 1200 सैन्यकर्मि हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें दोनों देशों के 600-600 सैनिक शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, युद्धभ्यास 2026 का मुख्य उद्देश्य दोनों सेनाओं के इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को पहाड़ी और अर्ध-पहाड़ी

इलाकों में प्रभावी ढंग से संयुक्त रूप से इस्तेमाल करने की क्षमता बढ़ाना है। इसमें पैदल सेना पर आधारित अभियानों की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि सैनिक एक-दूसरे के साथ मिलकर योजना बनाने, ऑपरेशनों को अंजाम देने और विभिन्न परिस्थितियों में बेहतर तालमेल बिठाने का अभ्यास कर सकें। इस दौरान दोनों सेनाएं अपनी रणनीति, तकनीक और युद्ध प्रक्रियाओं को साझा करेंगी। भारतीय सेना में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप (आईबीजी) एक नई और महत्वपूर्ण सैन्य संरचना है, जिसमें करीब 3000 से 4000 सैनिक होते हैं। इसमें पैदल सेना के साथ टैंक, तोपखाना, वायु रक्षा इकाइयां,

इंजीनियर और सिग्नल जैसी विभिन्न सहायता इकाइयां शामिल होती हैं। इसका मुख्य लाभ यह है कि जरूरत पड़ने पर अलग-अलग सैन्य क्षमताओं को एक ही फॉर्मेशन के तहत तेजी से इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय सेना ने इसी साल अपनी पहली आईबीजी संरचनाओं को ऑपरेशनल किया है। युद्धभ्यास 2026 की एक अहम बात नई सैन्य तकनीक का उपयोग है। अभ्यास के दौरान निगरानी के लिए ड्रोन और ऑटोनॉमस सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन भी होगा। दोनों देशों के सैन्य विशेषज्ञ

सेवा से संकल्प तक : बदलते भारत की मोदी- यात्रा

(लेखक – डॉ. प्रवीण दाताराम गुगनानी)

एक दशक से अधिक की वह यात्रा, जिसमें शासन का केंद्र समाज और राष्ट्र रहा

17 सितंबर की तिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मात्र नहीं है। यह उस राजनीतिक यात्रा को देखने का अवसर भी है, जिसने पिछले बारह वर्षों में भारत के शासन-विमर्श, विकास-दृष्टि और वैश्विक भूमिका को अनेक स्तरों पर प्रभावित किया है। 2014 में प्रारंभ हुई यह यात्रा अब उस पड़ाव पर है, जहाँ उपलब्धियों का उत्सव मनाने के साथ-साथ उनके दीर्घकालीन प्रभावों का मूल्यांकन भी आवश्यक है।

मोदी सरकार के बारह वर्षों को किसी एक योजना, एक निर्णय या एक राजनीतिक नारे से नहीं समझा जा सकता। इसका व्यापक स्वरूप जनकल्याण, जनभागीदारी, आत्मनिर्भरता, डिजिटल सशक्तीकरण, आधारभूत संरचना, सांस्कृतिक आत्मविश्वास और वैश्विक सक्रियता के सम्मिलित प्रयास के रूप में दिखाई देता है।

सबसे पहले शासन की उस शैली को देखना होगा, जिसने भारत के करोड़ों नागरिकों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम किया। जन-धन खाते, आधार और मोबाइल, इस JAM की त्रिमूर्ति ने कल्याणकारी योजनाओं के वितरण की संरचना को बदला। मार्च 2026 तक जन-धन खातों की संख्या 57.71 करोड़ और आधार की संख्या 144 करोड़ से अधिक हो चुकी थी। इसी डिजिटल आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और डिजिटल भुगतान का व्यापक विस्तार हुआ।

मार्च 2026 में अकेले UPI पर लगभग 2,264 करोड़ लेन-देन हुए, जिसका मूल्य ₹29.53 लाख करोड़ से अधिक था। आज भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली देश की सीमाओं से बाहर भी पहुँच रही है।

उज्ज्वला से स्वच्छ ईंधन, स्वच्छ भारत से शौचालय, जल जीवन मिशन से नल का जल, प्रधानमंत्री आवास से पक्का घर और आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य सुरक्षा, इन योजनाओं ने करोड़ों परिवारों को लक्षित किया।

सरकारी आकलनों के अनुसार 2014 के बाद शहरी कचरा प्रसंस्करण 16 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में 82 प्रतिशत हुआ और डोर-टू-डोर कचरा संग्रह 43 प्रतिशत से बढ़कर 98 प्रतिशत हुआ।

राष्ट्र निर्माण कार्य को विचारवान नेतृत्व के साथ-साथ सड़क, रेल, बिजली, जल और संचार चाहिए। मोदी सरकार ने पूंजीगत व्यय को विकास की केंद्रीय धुरी बनाया। इस धुरी का परिणाम रहा कि केंद्र का पूंजीगत व्यय 2014-15 के लगभग ₹2 लाख करोड़ से बढ़कर 2026-27 में ₹12.2 लाख करोड़ हो गया।

रेलवे में विद्युतीकरण विकास का प्रमुख उदाहरण है। मार्च 2026 तक ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका था। वंदे भारत जैसी रेल सेवाओं ने आधुनिक भारतीय रेल की नई आकांक्षा को प्रतीकात्मक रूप भी दिया है।

ऊर्जा के क्षेत्र में मार्च 2026 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 532 GW से अधिक हो चुकी थी, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 274.69 GW तक पहुँच गई। सौर ऊर्जा क्षमता 2014 के 2.82 GW से बढ़कर 150.26 GW हो गई है।

नरेंद्र मोदी जी की प्रथम अवधारणा रही है – ‘आत्मनिर्भर भारत’। इस ओर देखें तो हमें चित्र दिखता है कि भारत का रक्षा उत्पादन 2014-15 के ₹46,429 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹1.78 लाख करोड़ हो गया। रक्षा निर्यात ₹686 करोड़ से बढ़कर ₹38,424 करोड़ हो गया और भारतीय रक्षा उत्पाद 80 से अधिक देशों तक पहुँच रहे हैं। ‘सक्षम भारत’ का यह सर्वाधिक ज्वलंत उदाहरण है।

इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल निर्माण, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी इसी दृष्टि का विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने अगस्त 2026 में अपने संबोधन में पिछले बारह वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में लगभग सात गुना और मोबाइल फोन उत्पादन में 35 गुना वृद्धि का उल्लेख किया।

1 जुलाई 2017 को ऋस्झ का लागू होना भारतीय कर-व्यवस्था के इतिहास का बड़ा परिवर्तन था। अनेक अप्रत्यक्ष करों को एक साझा ढाँचे में लाने का यह प्रयास आर्थिक एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। ऋस्झ की युक्तियुक्तकरण की यात्रा अभी जारी है।

मोदी काल को केवल आर्थिक और प्रशासनिक परिवर्तनों से समझना अधूरा होगा। इस काल में सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय प्रतीकों को सार्वजनिक विमर्श में नई प्रमुखता मिली। अयोध्या में श्रीराम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा, काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्विकास, केदारनाथ सहित अनेक तीर्थस्थलों का विकास और भारत से बाहर

गई पुरावरस्तुओं की वापसी इसी व्यापक सांस्कृतिक विमर्श का हिस्सा है। यह सब आपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के विमर्श का मूर्तिरूप स्वरूप है। 7 रेशकोर्स से लोककल्याण का और राजपथ से कर्तव्य पथ का नामकरण एक बड़ा प्रतीक है।

2014 के बाद भारतीय विदेश नीति में सक्रियता और बहुपक्षीय मंचों पर भारत की भूमिका बढ़ी। 2023 की तऱ20 अध्यक्षता इसका महत्वपूर्ण उदाहरण बनी। नई दिल्ली घोषणा पर सहमति और अफ्रीकी संघ को तऱ20 का स्थायी सदस्य बनाए जाने की पहल ने भारत को ‘ग्लोबल साउथ’ के प्रश्नों को प्रमुखता से उठाने का अवसर दिया।

चंद्रयान-3 की सफलता ने भारत की वैज्ञानिक क्षमता को विश्व के सामने नए स्तर पर स्थापित किया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफल सॉफ्ट लैंडिंग ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए नया अध्याय खोला। अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी उद्यमों के लिए खोलने और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के प्रयासों ने विज्ञान को नई आर्थिक संभावनाओं से जोड़ने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है।

किसी भी लोकातांत्रिक सरकार का मूल्यांकन केवल उसके समर्थकों के उत्साह या विरोधियों की आलोचना से नहीं हो सकता। रोजगार की गुणवत्ता, कृषि की आय, शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता, सामाजिक समरसता, शहरी जीवन, छोटे उद्यमों की चुनौतियाँ और आर्थिक असमानता जैसे प्रश्न अभी भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

मोदी सरकार की बारह वर्ष की यात्रा को समझने का सबसे उचित तरीका न तो केवल प्रशस्ति है और न केवल आलोचना। यह उस परिवर्तन को पहचानना का प्रयास है, जिसमें राज्य की क्षमता, डिजिटल प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक आत्मविश्वास को एक व्यापक राष्ट्रीय परियोजना से जोड़ने का प्रयास हुआ है।

17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है। एक व्यक्ति का जन्मदिवस समय के साथ बीत जाता है, किंतु उसके नेतृत्व में लिए गए निर्णय संस्थाओं, नीतियों और सामाजिक मानस में दीर्घकालीन प्रभाव छोड़ सकते हैं।

मोदी सरकार के बारह वर्षों की सबसे बड़ी कथा शायद यही है कि भारत ने अपने बारे में बोलने की भाषा बदली है, याचक से सहभागी, आयातक से निर्माता, डिजिटल उपभोक्ता से डिजिटल



शक्ति और वैश्विक व्यवस्था के दर्शक से सक्रिय भागीदार बनने की आकांक्षा तक।

यह यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई है। ‘विकसित भारत’ का संकल्प अभी लक्ष्य है, उपलब्धि नहीं। इसलिए आगामी वर्षों की चुनौती यही होगी कि योजनाओं और घोषणाओं की ऊर्जा को रोजगार, उत्पादकता, सामाजिक समरसता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वैज्ञानिक नवाचार और प्रत्येक नागरिक के जीवन की वास्तविक समृद्धि में रूपान्तरित किया जाए।

जन्मदिवस पर सम्पूर्ण राष्ट्र की ओर से अभिनंदन, आद. प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जी! आप शतजीवी हैं।

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

नरेंद्र मोदी : युगदृष्टा नेतृत्व, सेवा से विकसित भारत तक

(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिन पर विशेष) –

(लेखक-/अलोक शर्मा

हम सब देशवासियों का सौभाग्य है कि हमें श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में ऐसा नेतृत्व मिला, जिसने राजनीति को सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि सेवा और राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाया। लोकसेवक के रूप में उनकी 25 वर्षों की यात्रा केवल शासन की यात्रा नहीं है, बल्कि यह सेवा, सुशासन, विकास, जनकल्याण और सामान्य नागरिक के जीवन में आए बदलाव की यात्रा है। वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुआ यह सफ़र आज विकसित भारत शऱ2047 के संकल्प तक पहुँच चुका है।

इन वर्षों में देश ने अनेक ऐसे परिवर्तन देखे हैं, जिनका प्रभाव समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में भी दिखाई देता है। गरीब, किसान, महिला, युवा, मध्यम वर्ग और वंचित परिवारों को केंद्र में रखकर बनाई गई योजनाओं ने विकास को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है।

कभी गरीब परिवार के लिए पक्का मकान एक सपना हुआ करता था। प्रधानमंत्री आवास योजना ने करोड़ों परिवारों को पक्के घर का सपना पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। घर के साथ शौचालय, स्वच्छता, बिजली, पानी और रसोई जैसी सुविधाओं ने जीवन की गरिमा को बढ़ाया। उज्ज्वला योजना ने करोड़ों महिलाओं को धूप से भरी रसोई से राहत दिलाने का काम किया। जनधन योजना ने गरीब और वंचित परिवारों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा, वहीं आयुष्मान भारत ने गंभीर बीमारी के समय गरीब परिवारों को उपचार की आर्थिक सुरक्षा का भरोसा दिया।

कोरोना महामारी जैसे कठिन दौर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से करोड़ों जरूरतमंद लोगों को मुफ़्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। जरूरतमंद परिवारों के लिए यह केवल राशन नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में घर का चूल्हा जलता रहने का भरोसा बना। यह योजना लगातार जारी है। इसी प्रकार किसान सम्मान निधि, मुद्रा योजना, स्वयं सहायता समूहों और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी पहलों ने आर्थिक अवसरों को व्यापक बनाने का प्रयास किया है।

प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता के आह्वान ने स्वच्छता को सरकारी कार्यक्रम से आगे बढ़ाकर जनआंदोलन का स्वरूप दिया। भोपाल में भानुपुर ख़ती में करीब 100 वर्षों से जमा कचरे के निष्पादन के बाद वहां हरित क्षेत्र विकसित किया गया। इसी तरह सूर्ययान कार्बाइड परिसर में गैस त्रासदी की भीषणतम औद्योगिक दुर्घटना के बाद दशकों से पड़े जहरीले कचरे के वैज्ञानिक निष्पादन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 126 करोड़ रुपये की राशि मग्न सरकार को उपलब्ध कराई गई। जिससे जहरीले कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन किया जा चुका है। यह भोपाल के पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में आर्थिक और कर व्यवस्था में भी बड़े बदलाव हुए हैं। जीएसटी ने देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एक साझा ढांचे में लाने का प्रयास किया। आयकर व्यवस्था में डिजिटल प्रक्रियाओं, ऑनलाइन सेवाओं और फेसलेस असेसमेंट जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से कर प्रशासन को अधिक तकनीक आधारित और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया। डिजिटल भुगतान और डिजिटल सार्वजनिक अवसरचना ने भी आम नागरिक के आर्थिक व्यवहार में नई सुविधाएं जोड़ी हैं।

भोपाल के विकास की बात करें तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के सहयोग से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति मिली है। राजा भोज सेतु और रानी कमलापति ब्रिज जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स ने शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में भूमिका निभाई है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण, भोपाल मेट्रो, सड़कों और अन्य आधारभूत परियोजनाओं का विस्तार राजधानी को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ रहा है। भोपाल के विकास की यह यात्रा आने वाले वर्षों में और व्यापक होने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता ने भी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। चंद्रयान-3 की सफलता ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की क्षमता को नई पहचान दी है। रेलवे विद्युतीकरण, वंदे भारत जैसी आधुनिक रेल सेवाओं, एक्सप्रेससेवे, मेट्रो, हवाई अड्डों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार ने देश की कनेक्टिविटी को नई गति दी है। क्षेत्रीय

हवाई संपर्क बढ़ाने के प्रयासों से छोटे शहरों को भी देश के बड़े शहरों से जोड़ने की दिशा में काम हुआ है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है, नक्सलवाद देश से खत्म हो चुका है। सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा क्षमता के विस्तार पर जोर दिया गया है। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों में बदलाव, तीन तलाक के खिलाफ कानून और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी इसी अवधि में हुए हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 25 वर्षों की लोकसेवा यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होंने सेवा को शासन की कार्यसंस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया। गरीब कल्याण से लेकर महिला सशक्तिकरण, किसान हित, युवा अवसर, डिजिटल भारत, स्वच्छता, आधारभूत संरचना और आत्मनिर्भरता तक, विकास की अनेक धाराओं को एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है।

इसी 25 वर्षों की सेवा यात्रा को जन-जन तक पहुंचाने और सेवा के संकल्प को सामाजिक भागीदारी से जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा ‘सेवा संकल्प अभियान’ आयोजित किया जा रहा है। ‘जन सेवा ही देशभक्ति’ की भावना के साथ 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘आशीर्वाद का दीया’, चित्रकला, भाषण एवं रंगोली प्रतियोगिताएं, कलश यात्रा, ‘सेवा ज्योति’ मशाल पदयात्रा, ‘सेवा मेरा योगदान’ और ‘सेवा सेतु’ जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

यह अभियान केवल 25 वर्षों की उपलब्धियों का स्मरण करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह सेवा से संकल्प और संकल्प से विकसित भारत की यात्रा को आगे बढ़ाने का अवसर है।

हमारा लक्ष्य है कि विकास और जनकल्याण की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, हर नागरिक को सम्मान और अवसर मिले और देश का प्रत्येक नागरिक विकसित भारत शऱ2047 के निर्माण में अपना योगदान दे।

सेवा की यह यात्रा निरंतर जारी रहे—यही संकल्प है, यही विकसित भारत की दिशा है।

लेखक — आलोक शर्मा, सांसद, भोपाल

प्रधानता आत्मा को

ही सत्य के दर्शन तथा यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि कर सकता है।

यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि हो जाने पर मनुष्य के सारे शोक-संतापों का स्वतः समाधान हो जाता है। अंतरात्मा की बात सुनना और मानना ही उसका अनुशासन है। मनुष्य की अन्तरात्मा बोलती है, किन्तु उसकी वाणी सूक्ष्मातिसूक्ष्म होती है, जिसे बाह्य एवं स्थूल श्रवणों से नहीं सुना जा सकता। मनुष्य की अन्तरात्मा बोलती है किन्तु मौन विचार स्फूर्ण की भाषा में, जिसे मनुष्य अपनी कोलाहलपूर्ण मानसिक स्थिति में नहीं सुन सकता। अन्तरात्मा की वाणी सुनने के लिए जरूरी है मनुष्य का मानसिक कोलाहल बन्द हो।

अन्तरात्मा का सांनिध्य मनुष्य को उसकी आवाज सुनने योग्य बना देता है। यों मनुष्य की अन्तरात्मा उसमें ओतप्रोत है, पर उसका सच्चा सांनिध्य पाने के लिए उसे जानना आवश्यक

है। परिचयहीन निकटता भी एक दूरी होती है। रेलयात्रा में कन्चे से कन्चा मिलाये बैठे दो आदमी अपरिचित होने के कारण समीप होने पर भी एक-दूसरे से दूर होते हैं। अजनबी छोड़िए, किन्दगी भर एक दूसरे केसाथ रहने पर भी आन्तरिक परिचय के अभाव में कई लोग एक-दूसरे से दूर ही रहते हैं। अन्तरात्मा जानने का एक ही उपाय है कि उसके विषय में सदा जिज्ञासु तथा सचेत रहा जाए। जो जिसके विषय में जितना अधिक जिज्ञासु एवं सचेत रहता है, वह उसकेविषय में उतनी ही गहरी खोज करता है और निश्चय ही उसे पा लेता है। आत्मा के विषय में अधिक से अधिकजिज्ञासु एवं सचेत रहिए। अपनी आत्मा से परिचित होंगे, उसकी वाणी सुनेंगे, सच्चा मार्ग निर्देशन पाएंगे, तो अज्ञान से मुक्त हों यथार्थ सुख-शान्ति के अधिकारी बनेंगे।

(पर्यूषण पर्व पर विशेष) झुको और झोली भरो। (उत्तम मार्दव)

(लेखक- मुनि विशोक सागर)

मान-नरक का द्वार है, अहंकार पतन का कारण है जबकि नम्रता-विनय उत्थान का कारण है। अहंकार व्यक्ति को कठोर बनाता है जबकि नम्रता मुलायम बनाती है, अहंकारी व्यक्ति दुनिया को झुकाना चाहता है स्वयं झुकना नहीं चाहता, जो दुनिया को तो झुकाना चाहता है स्वयं नहीं झुकना चाहता वह अभिमानी है और अभिमान के विसर्जन से ही जीवन में धर्म का सूत्रपात होता है। अहंकार को मिटा देना ही बनने और बढ़ने का मार्ग है। जब तक अहंकार नहीं मिटाओगे तब तक जीवन नहीं बन सकता। झुकने की कला आ जाना ही सम्पूर्ण का प्रथम सूत्र है। जिसके पास नम्रता है उसके पास सम्पूर्ण शक्तियाँ हैं, जिसके पास नम्रता, प्रेम, वात्सल्य नहीं उससे बड़ी शक्तियाँ भी टूट जाती हैं। चाहे उरीब हो, चाहे अमीर हो, राजा हो या रंक सभी को मृत्यु बेला में लकड़ियों पर

आकर जलना पड़ता है। सभी को श्मसान भूमि मरघट पर जलना पड़ेगा। फिर अहंकार के शिखर पर क्यों चढ़ना चाहते हो। दौलत का अर्थ है, जो दो लातें लगाकर तुम्हें गिरा दे वह है दौलत का अभिमान। तुम्हें में को गिरा देना है। नम्रता का अर्थ सिर्फ बाहर से झुकना नहीं अपितु अंदर एवं बाहर दोनों ओर से नम्रभाव आ जाना ही वास्तविक नम्रता है। अहंकार में कभी भी परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं अहंकार खोकर ही परमात्मा को पाया जा सकता है। आराध्य या पूज्य पुरुषों के प्रति झुकोगे तभी तुम धर्म से भर पाओगे बाल्टी जब झुकती है तभी जल से भरती है। आचार्य कार्तिकेय स्वामी जी कहते हैं- उत्तम पाण-पहाणो, उत्तम तवचरण करण सीलो वि, अपाणों जो हीलदि सदृदेव-स्थयं देवे तस्स। उत्तम ज्ञान में भी प्रमुख प्रधान है, वह है उत्तम मार्दव धर्म। उत्तम ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, वह है उत्तम मार्दवधारी, उत्तमशील धारियों में भी श्रेष्ठ है-उत्तम मार्दव वाला, तपस्व्या में भी प्रथम है इन

तीनों से श्रेष्ठ उत्तम मार्दव धर्म है। मृदुभावः मार्दवः मृदु स्वभाव अर्थात कोमल परिणाम तथा नम्र भाव का नाम है-मार्दव, जब तक अभिमान है, तब तक तपश्चरण या साधना की उपलब्धि संभव नहीं। अभिमान व्यक्ति के पतन का कारण है। आत्मा को धूमिल एवं अपवित्र करने वाला है। मार्दव आत्मा का स्वभाव है जहाँ से विम्रता, म्रता, लालचीपन स्वतः ही आ जाता है। वहाँ से मार्दव का प्रादुर्भाव होता है। मान एक कषाय है जो आत्मा को गंवा करता है। मान में दो शब्द मा का अर्थ है = मार्ग एवं न का अर्थ है = नरक, जो मार्ग नरक का हो वह है मान। मान ही तो नरक का द्वार है, मान व्यक्ति को झुकने नहीं देता अपितु दुनिया को झुकाना चाहता है। झुकने की कला जब तक नहीं आयेगी तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। सम्पूर्ण का प्रथम पाठ है – झुकना सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी। झुकना बाहर के झुकने में भी अभिमान छिपा रहता है। एक व्यक्ति घोषणा करता है कि

हम अपने नाम की पटिया नहीं लगावायेगे किन्तु सभा में घोषणा वीडियो, फोटो आदि की चाहना है। आज का व्यक्ति धार्मिक कार्यों में भी अहंकार नहीं छोड़ता। मंदिर या धर्मस्थान में अभिमान-पोषण चाहता है। यह कितनी बड़ी अज्ञानता है। यह तो पाप की पुष्टि करना है। आराध्य या गुरुओं के चरणों में अपने जीवन को अर्पण कर दो। झुके बिना आप भर नहीं सकते। बर्तन को नल के नीचे आना पड़ेगा तभी वह पानी से भर सकता है। धन-दौलत के नशे में, व्यक्ति अहंकार की ऊँचाइयों में उड़ान-भरने लगता है। दौलत का अर्थ है – जो दो लातें मारकर तुम्हें जमीन की धूल चटा दे। दौलत का अहंकार तुम्हें नरक में ले जायेगा। इसलिए कभी भी अहंकार तुम्हें मिट्टी में मिला देगा। जिस शरीर को तुम सुन्दर कहकर अहंकार करते हो वह भी अग्नि में स्वाहा हो जायेगा। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं रखना। जीवन में नम्रता लाओ। नम्रता तुम्हें तार देगी, संसार से पार लगा देगी। नम्रता से उपलब्धि है

तो अहंकार से दुर्गति है। राम और रावण का प्रसिद्ध दृष्टान्त है – एक लाख पुत्र सवा लाख नाती जिसके घर से दिया न बांती, यह मात्र अहंकार का परिणाम है। आज विद्वान, विद्वान को नीचा दिखाना चाहता है, एक दूसरे को सदा नीचा दिखाने हेतु प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि मेरी ही प्रतिष्ठा सम्मान होनी चाहिए और अन्य की नहीं। पुरानी दीवार को तोड़ नई तैयार करो, अहंकार की दीवार तोड़कर नम्रता के दीवाल तैयार करो – मिटना पड़ेगा तभी बनेगे, फिर से नयी बुनियाद को भरना पड़ेगा, तभी बनेगे। जन्म से तो अहंकार रुपी नाग पाल रखा है। उसे छोड़ना होगा तभी तुम्हें मुक्ति रुपी मंजलि की प्राप्ति होगी। नो पैन नो गैन, बिना कष्ट के मुक्ति नहीं। बिना कष्टों के उपलब्धियाँ सम्भव नहीं। बनने के लिए मिटना होगा। बूँद जब मिटती है तो सागर बन जाया करती है। मिट्टी जब मिटती है तो गागर बन जाया करती है। सम्पूर्ण ही मानव को भगवान बना देता है।

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का भारत दौरा सरकार की मंजूरी पर निर्भर: पीएचएफ



नई दिल्ली । पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन (पीएचएफ) के प्रमुख मोहिउद्दीन अहमद वानी ने कहा है कि अगले महीने होने वाली हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का भारत दौरा

सरकार की मंजूरी पर निर्भर है। मेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जालंधर और मोहाली में होगी। इसमें भारत, चीन, जापान, मलेशिया और कोरिया के साथ हो

पाकिस्तान को भी हिस्सा लेना है। पाकिस्तान के नहीं आने की स्थिति में ओमान या बांग्लादेश को मौका दिया जा सकता है। दोनों टीमों को फिलहाल रिजर्व टीम के रूप में रखा गया है। पाकिस्तान के दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र 'डॉन' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वानी ने कहा, 'पाकिस्तान टीम का दौरा सरकारी मंजूरी पर निर्भर करेगा। सरकार हमसे जो भी करने को कहेगी, हम वही करेंगे।'

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान अगले महीने टूर्नामेंट के लिए भारत आएगा। मल्टी-नेशनल टूर्नामेंट में कोई दिक्कत नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं हो सकती।

उन्होंने केंद्र सरकार की नीति का जिक्र करते हुए बताया कि भारत और पाकिस्तान मल्टीनेशनल इवेंट्स में हिस्सा ले सकते हैं।

ओल्ड ट्रैफर्ड में खेलना मेरे लिए बड़ा पल, जिंदगी में इतना बड़ा स्टेडियम कभी नहीं देखा था: टिलेमैन्स

नई दिल्ली । मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के नए मिडफील्डर यूरी टिलेमैन्स का कहना है कि ओल्ड ट्रैफर्ड में

खेलना फुटबॉल के सबसे खास अनुभवों में से एक है। उन्होंने याद किया कि जब वह एस्टन विला के लिए खेलते थे और पहली बार विरोधी खिलाड़ी के रूप में इस प्रतिष्ठित स्टेडियम में उतरे थे, तो वहां का माहौल देखकर काफी प्रभावित हुए थे। जुलाई में, मिडफील्डर ने जून 2031 तक मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। पिछले सीजन में उन्होंने एस्टन विला के लिए सात असिस्ट किए और अपने क्लब को यूईएफए यूरोपा लीग जीतने में मदद की, जिसमें उन्होंने एएससी प्रीमियर के खिलाफ फाइनल में पहला गोल किया। उन्होंने जियोहॉटस्टार को बताया, 'मैनचेस्टर यूनाइटेड एक बहुत बड़ा क्लब है। ओल्ड ट्रैफर्ड में पहली बार विरोधी

टीम के तौर पर खेलना मेरे लिए एक बड़ा पल था। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा स्टेडियम कभी नहीं देखा था। माहौल, भीड़, इसके बारे में सब कुछ कमाल का था। यह ऐसी जगह है जहां हर फुटबॉलर खेलने का सपना देखता है।'

बेल्जियम के स्टार मिडफील्डर यूरी टिलेमैन्स अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी के रूप में ओल्ड ट्रैफर्ड के माहौल का अनुभव करने के लिए उत्साहित हैं। यूनाइटेड 2026-27 प्रीमियर लीग सीजन में मिश्रित शुरुआत के बाद लय हासिल करने की कोशिश कर रहा है। टीम ने लीग के अपने पहले चार मैचों में चार अंक जुटाए हैं। यूनाइटेड को हल सिटी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, इसके बाद

टीम ने इप्सविच टाउन को 5-2 से हराया। वहीं, एवर्टन के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ रहा, जबकि मैनचेस्टर डर्बी में उसे मैनचेस्टर सिटी से 0-1 की हार मिली।



संक्षिप्त समाचार

पूर्व बार्सिलोना स्टार फिलिप कूटिन्हो दिसंबर तक सैंटोस एफसी से जुड़े



सैंटोस । ब्राजीलियाई क्लब सैंटोस एफसी ने लिवरपूल और बार्सिलोना के पूर्व प्लेमेकर फिलिप कूटिन्हो को 'फ्री ट्रांसफर' पर साइन किया है। क्लब ने मंगलवार को यह घोषणा की। 34 वर्षीय खिलाड़ी का यह कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर तक के लिए है। सैंटोस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'अपनी बेहतरीन तकनीकी गुणवत्ता और दृष्टिकोण के साथ-साथ यूरोप और ब्राजीलियाई राष्ट्रीय टीम के साथ शानदार करियर वाला यह मिडफील्डर 2026 के अंत तक के कॉन्ट्रैक्ट के साथ टीम में शामिल हो रहे हैं।' फरवरी में मानसिक थकान का इलावा देते हुए 'वासको दा गामा' से अलग होने के बाद कूटिन्हो किसी क्लब के साथ नहीं थे। कूटिन्हो के मुताबिक, उन्हें क्लब में लाने में उनके पुराने दोस्त नेमर ने अहम भूमिका निभाई है। दोनों ब्राजील के लिए यूथ और सीनियर दोनों स्तरों पर एक साथ खेल चुके हैं, जिसमें फीफा वर्ल्ड कप 2018 भी शामिल है।

भारत में फॉर्मूला वन की वापसी की तैयारी, सरकार ने टास्क फोर्स का किया गठन



नई दिल्ली । भारत में फॉर्मूला वन और मोटर स्पोर्ट्स को फिर से जीवित करने और उसके विकास के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य भारत में मोटर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का व्यापक मूल्यांकन करना है। साथ ही, ट्रैक्स से जुड़े मुद्दों सहित उन सभी चुनौतियों की समीक्षा करना है, जो भारत में मोटर स्पोर्ट्स के रिवाइवल और विकास को प्रभावित कर रही हैं। टास्क फोर्स के लिए काम के दायरे यानी टर्मस ऑफ रेफरेंस भी तय किए गए हैं। पहला, भारत में मोटर स्पोर्ट्स के सतत विकास के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों की पहचान करना और एक समय और समन्वित रोडमैप तैयार करना है। दूसरा, भारत के मोटर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विस्तृत मूल्यांकन करना और मोटर स्पोर्ट्स इवेंट्स के रिवाइवल और विकास से जुड़ी चुनौतियों की समीक्षा करना, जिसमें ट्रैक्सेशन भी शामिल है।

यूईएफए ने 2028 और 2029 चैंपियंस लीग फाइनल के टेन्यू किए तय

म्यूनिख और कैप नोउ को मिली मेजबानी

न्योन । यूईएफए ने 2028 और 2029 चैंपियंस लीग फाइनल के आयोजन स्थलों की पुष्टि कर दी है। म्यूनिख फुटबॉल एरिना और बार्सिलोना का कैप नोउ प्रतिष्ठित यूरोपीय क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल की मेजबानी करेंगे। 2028 का खिताबी मैच म्यूनिख फुटबॉल एरिना में खेला जाएगा, जबकि 2029 संस्करण बार्सिलोना के कैप नोउ में होगा। म्यूनिख के स्टेडियम को प्रमुख चैंपियंस लीग आयोजनों की मेजबानी करने का काफी अनुभव है। इसने साल 2012 में और फिर 2025 में फाइनल का आयोजन किया, जबकि 2028 संस्करण इस आयोजन स्थल को यूरोप के शीर्ष क्लबों का स्वागत करने का एक और मौका देगा। बार्सिलोना के लिए 2029 का फाइनल चैंपियंस लीग के प्रतिष्ठित मुकाबले की कैप नोउ में तीन दशक बाद वापसी का प्रतीक होगा।

संजू-अभिषेक के बीच 88 रन की तूफानी साझेदारी

जीता भारत

सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त

नई दिल्ली । भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ मंगलवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया दूसरा टी20 मैच 7 विकेट से अपने नाम किया। इसी के साथ टीम इंडिया ने तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। अंतिम मुकाबला 17 सितंबर को इसी मैदान पर खेला जाना

जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई को 1-1 विकेट हाथ लगा।

इसके जवाब में, टीम इंडिया ने 14.5 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सलामी जोड़ी ने जोड़ी ने विस्फोटक शुरुआत दिलाई। दोनों



है। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी अफगान टीम ने खराब शुरुआत के बावजूद 8 विकेट खोकर 159 रन बनाए। इस टीम को 1.3 ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज (0) के रूप में शुरुआती झटका लगा। उस समय तक खाता भी नहीं खुला था। इसके बाद कसान इब्राहिम जादरान ने सेविकुल्लाह अटल के साथ दूसरे विकेट के लिए 51 रन जुटाकर अफगानिस्तान को संभालने की कोशिश की, लेकिन जादरान (37) के आउट होने के बाद टीम लड़खड़ा गई। आलम ये रहा कि 100 के स्कोर तक 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए।

यहां से मोहम्मद नबी (20) और राशिद खान (28) की अनुभवी जोड़ी ने मोर्चा संभाला। इन बल्लेबाजों ने सातवें विकेट के लिए 28 गेंदों में 48 रन की साझेदारी करते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया।

भारत के लिए नितीश रेड्डी ने 3 विकेट हासिल किए, जिन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया, जबकि अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट निकाले। इनके अलावा,

खिलाड़ियों ने 38 गेंदों में 88 रन की साझेदारी की।

अभिषेक 19 गेंदों में 4 छक्कों और 2 चौकों के साथ 39 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद संजू ने ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 4 गेंदों में 11 रन की साझेदारी की।

भारत को 99 के स्कोर पर संजू सैमसन के रूप में दूसरा झटका लगा, जो 22 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 4 छक्के और 7 चौके शामिल रहे।

यहां से ईशान ने कसान श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 22 गेंदों में 24 रन जुटाए। अय्यर 11 गेंदों में इतने ही रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद ईशान ने तिलक वर्मा के साथ चौथे विकेट के लिए 25 गेंदों में 40 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई।



पहला वनडे

रेनेशों का शतक, एलिस का पंजा, ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे को 59 रन से हराया

हरारे । ऑस्ट्रेलिया ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में मंगलवार को खेले गए पहले वनडे मैच में जिम्बाब्वे को 59 रन से हराया। इसी के साथ मेहमान टीम ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है। सीरीज के शेष मुकाबले 18 और 20 सितंबर को खेले जाने हैं। टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर



294 रन बनाए। इस टीम को 10 के स्कोर पर ट्रेविस हेड (4) के रूप में पहला झटका लगा गया था, जिसके बाद कसान मिवेल मार्श ने कूपर कोनोली के साथ दूसरे विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी की। मार्श 28 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों के साथ 36 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद जोश इंग्लिस मैदान पर उतरे, लेकिन टीम के खाते में 4 रन से ज्यादा नहीं जोड़ सके। हालांकि, कूपर (51 रन) अर्धशतक लगाने में सफल रहे। टीम को 107 के स्कोर पर चौथा झटका लग गया था।

दूसरा टी20

कैटी मैक का तूफान

भारतीय टीम को 30 रन से मात देकर ऑस्ट्रेलिया-ए की सीरीज में अजेय बढ़त

न्यू चंडीगढ़ । ऑस्ट्रेलिया-ए ने भारत-ए के खिलाफ मंगलवार को न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अनाधिकारिक टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले

को 30 रन से अपने नाम किया। इसी के साथ मेहमान टीम ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया-ए ने सीरीज का पहला मैच 6 विकेट से अपने नाम किया था। अब अंतिम मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाएगा। मंगलवार को ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। कैटी मैक और रैचल ट्रेनानम की जोड़ी ने मेजबान टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों के बीच पहले विकेट के लिए 9 ओवरों में 75 रन की साझेदारी हुई।

रेचल 25 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 37 रन बनाकर पवेलियन लौटीं, जिसके बाद कैटी ने चालीं नॉट के साथ दूसरे विकेट के



लिए 38 रन जोड़े। चालीं 20 गेंदों में 4 बाउंड्री के साथ 26 रन बनाकर आउट हुईं। यहाँ से अनिका लीरॉयड ने कैटी के साथ तीसरे विकेट के लिए 65 रन जुटाकर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया।

कैटी 60 गेंदों में 83 रन बनाकर नाबाद रहीं। उनकी इस पारी में 11 चौके शामिल रहे, जबकि अनिका ने 16 गेंदों में 24 रन की नाबाद पारी खेली। भारत की तरफ से दोनों विकेट नंकी प्रसाद के हाथ लगे।

इसके जवाब में भारतीय टीम निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर 148 रन ही बना सकी। टीम को 9 के स्कोर पर दिनेश वृंदा (1) के रूप में शुरुआती झटका लगा, जिसके बाद शिप्रा गिरी ने सुजाता के साथ दूसरे विकेट के लिए 16 रन की साझेदारी की, लेकिन 29 के स्कोर तक सुजाता (8) के साथ शिप्रा (13) भी पवेलिन लौट गईं।

भारतीय टीम में विकेटों का पतझड़ लग गया था। आलम ये रहा कि 54 रन तक 5 विकेट गिर गए थे। इसके बाद नंकी प्रसाद ने मिन्नु मणि (16) के साथ छठे विकेट के लिए 53 रन और तनुजा कंवर (16) के साथ सातवें विकेट के लिए 35 रन जोड़े, लेकिन ये साझेदारियां जीत के लिए नाकामी थीं। नंकी 31 गेंदों में 2 छक्कों और 6 चौकों के साथ 54 रन बनाकर नाबाद रहीं।

विमेंस टी20 रैंकिंग: 800 रैंकिंग के साथ श्री चरणी ने

टी20 फॉर्मेट में इतिहास रचा

दीप्ति चार पायदान ऊपर चढ़ीं



रैंकिंग हासिल करने वाली तीसरी गेंदबाज हैं; उनसे पहले पूर्व नंबर 1 सोफी एक्लेस्टोन 802 रैंकिंग तक पहुंच चुकी थीं।

एक तरफ, चरणी शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर रही हैं, तो दूसरी ओर स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा उनकी जगह के लिए एक मजबूत दावेदार के तौर पर उभरी हैं। दीप्ति ने एशिया कप फाइनल में 19 रन देकर 3 विकेट लिए और 14 विकेट के साथ टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनीं। वह चार

पायदान ऊपर चढ़कर 729 रैंकिंग के साथ गेंदबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। हालांकि, हमबतन खिलाड़ी चरणी से काफी पीछे हैं। फाइनल में मैच जिताऊ 68 रन की पारी खेलने के बाद शेफाली वर्मा टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में एक पायदान ऊपर चढ़कर छठे स्थान पर पहुंच गई हैं। इसके साथ ही, शेफाली टी20 अंतरराष्ट्रीय ऑल-राउंडर्स की सूची में भी पांच स्थान ऊपर चढ़कर 15वें नंबर पर पहुंच गईं।



ताजमहल कैसे पहुंचें?

आगरा भारत का एक प्रमुख शहर है। इसलिए हवाई मार्ग हो या रेल मार्ग हो या फिर सड़क मार्ग। आगरा भारत वर्ष के सभी प्रमुख शहरों से सभी मार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ा है।

हवाई मार्ग

अगर आप हवाई मार्ग द्वारा आगरा जा रहे है तो आगरा का पंडित दीनदयाल उपध्याय हवाई अड्डा ताज महल से 16 किमी की दूरी पर स्थित है। यहां से आप आसानी से टैक्सी या आटो द्वारा आसानी से ताजमहल पहुंच सकते है। महानगर होने के नाते यहां काफी ट्रैफिक रहता है। जिसके कारण आपको आगरा एयर पोर्ट से ताजमहल पहुंचने में लगभग 40 मिनट लग सकते है, अगर ट्रैफिक न हो तो यह मार्ग सिर्फ 20-25 मिनट का है।

रेल मार्ग

यदि आप रेल मार्ग द्वारा आगरा जा रहे है तो आगरा कोर्ट रेलवे स्टेशन से ताजमहल की दूरी लगभग 2.5 किमी है। रेलवे स्टेशन से ताजमहल के लिए ऑटो और रिक्शा वालों की काफी भीड़ लगी रहती है। अगर आपके पास भारी लगेज नहीं है तो आप आगरा के किले का बाहरी भाग के दर्शन करते हुए किले के सामने से होते हुए शिवाजी चौक से ताजमहल पहुंच सकते है। शिवाजी चौक से ताजमहल का सेप्रेट रास्ता गया है, जो पश्चिमी गेट पर जाता है। कार, टैक्सी या ऑटो से आने वाले यात्री भी इसी मार्ग से जाते है। इसी सेपरेट मार्ग पर कुछ दूरी पर ताजमहल कार पार्किंग है।

सड़क मार्ग

अगर आप कार द्वारा दिल्ली से आगरा जा रहे है तो नोयडा आगरा एक्सप्रेस वे से जा सकते है। यह सुविधाजनक एवं फास्टेट रूट है। इसके आलावा आप दिल्ली से मथुरा होते हुए पुराने हाइवे से भी आगरा पहुंच सकते है।

कार पार्किंग

ताजमहल कार पार्किंग से ताजमहल की दूरी लगभग 700-800 मीटर है। आप चाहे एयर पोर्ट से टैक्सी से जाए या रेलवे स्टेशन से ऑटो से जाए या फिर अपनी कार से जाएं पहुंचना आपको कार पार्किंग में ही है। कार पार्किंग पर पहुंचते ही आपको ऊंट गाड़ी और बैट्री गाड़ी वाले घेर लेंगे, क्योंकि कार पार्किंग से ताजमहल के बीच की इस दूरी में बैट्री गाड़ियां व ऊंट गाड़ियां चलती है, जो बीस से तीस रुपए प्रति सवारी लेते है। कार पार्किंग से आगे किसी भी तरह के प्राइवेट वाहनों के जाने की अनुमति नहीं होती है। आप कार पार्किंग से ताजमहल गेट तक पैदल भी जा सकते है। 700 मीटर की दूरी कोई ज्यादा नहीं होती है।

अमानती घर

मार्ग के रास्ते में स्थित अमानती घर में आप अपना सामान रख सकते है, क्योंकि ताजमहल के अंदर किसी भी प्रकार का अटैची, बैग (हेड बैग को छोड़कर) किसी भी तरह का खाने-पीने का सामान खाना, बिस्कुट, चिप्स, पान, बीड़ी, सिगरेट (पानी की बोतल को छोड़कर) किसी भी तरह का हथियार चाकू व नशीले पदार्थ आदि अंदर ले जाना मना है। मोबाइल और कैमरा ले जा सकते है। बाकी आपके पास जो सामान है, उसे आप अमानती घर में सुरक्षित रख सकते है।

शूज कवर

यही टिकट खिडकी के पास ही आपको शूज कवर बेचने वाले भी मिल जाएंगे। उनसे आप बीस रुपए देकर शूज कवर खरीद लें, क्योंकि ताजमहल के संगमरमर के चबूतरे पर जूते-चप्पल लेकर जाना मना है। वहीं टिकट खिडकी के पास आपको गाइड और फोटोग्राफर घेर लेंगे, जो आपको कई तरह के प्रलोभन भी देंगे (जैसे – सॉटकेट से अंदर ले जाना का) क्योंकि एंट्री गेट पर चैकिंग प्वाइंट पर काफी लंबी कतार होती है या तो आप उनसे सही एवं पहले ही मोल-भाव कर तय कर लें या फिर टिकट कांटर से पर्यटन विभाग द्वारा गाइड हायर कर सकते है। चैकिंग प्वाइंट पर महिला, पुरुष व विदेशियों की अलग-अलग लाइनें होती है। यहां ज्यादा समय नहीं लगता 20-25 मिनट में आप अंदर पहुंच सकते है।

अलग-अलग प्रवेश द्वार

ताजमहल में एंट्री करने के लिए तीन गेट्स हैं, जो पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में मौदूद हैं। इन तीनों गेट्स में जिस गेट पर लोगों की भीड़ सबसे कम होती है वह है इसका पश्चिमी गेट। इस गेट से आप आसानी से ताजमहल के परिसर में एंट्री कर सकते हैं।

शुक्रवार को न जाएं ताजमहल

आमतौर पर ताजमहल रोजाना सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खुला रहता है, लेकिन शुक्रवार को इसे नमाज के लिए बंद रखा जाता है। पूर्णमासी के दिन ताजमहल के गेट्स रात 8.30 बजे से 12.30 बजे तक खुले रहते हैं। चांद की रोशनी में ताजमहल बेहद खूबसूरत लगता है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि रमजान के पवित्र महीने में आप रात के वक्त ताजमहल का दीदार नहीं कर सकते।

ताजमहल के बारे में रोचक बातें, जो आपको नहीं होंगी पता

ताजमहल मुगल वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट नमूना है। मोहब्बत की इस निशानी को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनाया था। दुनियाभर से करोड़ों की संख्या में पर्यटक ताजमहल देखने के लिए आगरा आते हैं। हर प्रेमी जोड़े की खातिर होती है कि वह ताजमहल जाकर अपनी प्रेमिका के साथ तस्वीर खिंचवाए। इश्क की इस निशानी को निहारें, संगमरमर की इमारत की खूबसूरती को अपनी स्मृतियों में कैद कर लें। आइए आपको ताजमहल के बारे में 10 रोचक बातें बताते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी।

- ताजमहल के निर्माण में 22 साल लगे थे।

- 22,000 से ज्यादा मजदूरों ने ताजमहल के निर्माण में काम किया था।

- 1,000 हाथियों के जरिए ताजमहल के निर्माण सामग्री को लाया गया था।

- ताजमहल के निर्माण में उस वक्त 3.2 करोड़ रुपए का खर्च आया था।

- ताजमहल के निर्माण के लिए विभिन्न एशियाई देशों से बहुमूल्य पत्थरों को लाया गया था।

- 28 तरह के रत्नों को श्रीलंका से लेकर चीन और भारत के विभिन्न राज्यों से लाया गया था।

- संगमरमर के सफेद पत्थर को राजस्थान से लाया गया था।

- तिब्बत से नीला रत्न, श्रीलंका से पन्ना, पंजाब से जैस्पर और क्रिस्टल को चीन से मंगाया गया था।

- ताजमहल की वास्तु शैली में फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण है।

- ताजमहल का निर्माण 1632 ईश्वी में शुरू हुआ था और 1653 में गुम्बद बनकर तैयार हुआ।

- अगर आप भी मुहब्बत की इस सबसे विश्व प्रसिद्ध निशानी को देखना चाहते हैं तो ताजमहल जरूर जाएं।

- आप दिल्ली में रहते हैं तो सिर्फ ताज एक्सप्रेस हाईवे से सिर्फ साढ़े तीन घंटे में आगरा पहुंच सकते हैं।

क्या सच है कि काला ताजमहल भी होता ?:

ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि शाहजहां यमुना के किनारे काले संगमरमर में ताजमहल की प्रतिकृति बनाना चाहते थे। शाहजहां को यह विचार जीन-बैप्टिस्ट टैवर्नियर नाम के एक यूरोपीय यात्री ने दिया था, जो 1665 में आगरा में था। दावा यह भी किया जाता है कि औरंगजेब के कारण शाहजहां की योजना पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया था। यमुना नदी से लगे महाताब बाग में कुछ काले मार्बल देखे भी गए थे, लेकिन बाद में जांच परख के बाद इतिहासकारों और आर्कैलॉजिस्ट सोसाइटी ने इस बात का खुलासा किया कि दरअसल महाताब बाग में मिले काले मार्बल गंदगी के कारण काले पड़ गए हैं। वह मूल रूप से सफेद ही थे, इसलिए यह बात अफवाह से कम नहीं कि शाहजहां काले ताजमहल भी बनवाना चाहता था।

क्या सचमुच कारीगरों के हाथ काटे गए थे?

ताजमहल के बारे में यह कहा जाता है कि उसने ताजमहल बनाने वाले सभी कारीगरों के हाथ काट दिए थे और कुछ को मार भी दिया था, लेकिन इतिहास में कहीं भी इस बात का साक्ष्य नहीं पाया गया।

ताजमहल को उजाड़ना चाहते थे अंग्रेज?

ताजमहल से जुड़ी कहानियों में एक नाम और आता है, भारत के गर्वनर जनरल लॉर्ड विलियम बेन्टिक का। कहा जाता है कि लॉर्ड ताजमहल को गिराना चाहता था और उसके मार्बल की नीलामी करना चाहता था। इस बात के भी कहीं सबूत नहीं पाए गए। हालांकि उसके बायोग्राफर जॉन रोसेली ने अपनी किताब में एक जगह लिखा है कि आगरा फोर्ट को बनाने के बाद बचे हुए मार्बल्स को लॉर्ड ने नीलाम कर दिया था।

ताजमहल में लगा है एक लैंप

ताजमहल में एक लैंप लगा हुआ है। कहा जाता है कि इसे बनाने में दो वर्ष का वक्त लगा था। इसे खास ताजमहल की नक्काशी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। इसे मिश्र के कुछ कलाकार और टोब्रैस बदीर नाम के आर्टिस्ट ने मिलकर बनाया था।

ताजमहल के रहस्य



- आपको यह जानकर हैरानी होगी की ताजमहल का आधार (नींव) लकड़ी पर टिकी है। इस लकड़ी की खासियत यह है कि यह लकड़ी जितनी पानी में रहती है, उतनी ही ज्यादा मजबूत होती है। यमुना नदी का पानी आज भी इस लकड़ी को मजबूत करता है।

- ताजमहल की छत में एक छेद है, जिसमें से बरसात के समय आज भी पानी टपकता है। इसके बारे में एक दंतकथा प्रचलित है कि शाहजहां ने ताजमहल बनने के बाद सभी कारीगरों के हाथ कटवाने का ऐलान कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि शाहजहां



गुजर जाने के बाद उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। कहा जाता है कि मुमताज महल ने मरते वक्त मकबरा बनाए जाने की खाहिश जताई थी, जिसके बाद शाहजहां ने ताजमहन बनावाया। ताजमहल को सफेद संगमरमर से बनवाया गया है। इसके चार कोनों में चार मीनारें हैं। शाहजहां ने इस अद्भुत चीज को बनवाने के लिए बगदाद और तुर्की से कारीगर बुलवाए थे। माना जाता है कि ताजमहल बनाने के लिए बगदाद से एक कारीगर बुलवाया गया, जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था।

इसी तरह बुखारा शहर से कारीगर को बुलवाया गया था, वह संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में दक्ष था। वहीं गुंबदों का निर्माण करने के लिए तुर्की के इस्तम्बुल में रहने वाले दक्ष कारीगर को बुलाया गया और मिनारों का निर्माण करने के लिए समरकंद से दक्ष कारीगर को बुलवाया गया था और इस तरह अलग-अलग जगह से आए करीगरों ने ताजमहल बनाया था।

ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है।

ताजमहल की

खूबसूरती को देखने

के लिए दुनियाभर से

लोग आते हैं और

अगर आप भारत में

रहकर भी अब तक

ताजमहल नहीं देख

पाए हैं तो अब और देर

न करिए। जितनी

जल्दी हो सके जाएं

और देखकर आएं, इस

ऐतिहासिक इमारत की

खूबसूरती ने दुनियाभर

के लोगों को अपना

दीवाना बनाकर रखा

है। इससे पहले की

आप ताजमहल घूमने

का प्लान बनाएं, हम

यहां आपको इससे

जुड़ी कुछ जरूरी बातें

बता देना चाहते हैं,

जिससे की आपकी यह

यात्रा बिना किसी

परेशानी बिल्कुल

आराम से बीते...

आगरा के अन्य

दर्शनीय स्थल

आगरा में ताजमहल के अलावा अन्य दर्शनीय स्थल हैं, जो बरबस यहां आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इनमें प्रमुख हैं-

आगरा का ताल किला: जिस स्थान पर आगरा का किला स्थित है, बहुत समय पहले यहां बादलगढ़ का किला हुआ करता था। हालांकि समय के साथ-साथ वह किला नष्ट हो गया था। मुगल सम्राट अकबर ने 1563 ई. से 1573 ईस्वी तक लगभग 8 वर्षों में बादलगढ़ किले के ध्वंस अवशेषों पर इस किले का निर्माण करवाया था। मुगल सम्राट अकबर ने इस किले में अकबरी महल, जहांगीरी महल, प्राचीर तथा प्रवेश द्वार अकबर ने बनवाए थे, जबकि शीश महल, खास महल, दीवाने आम और दीवाने खास तक मोती मस्जिद का निर्माण अकबर के पोते सम्राट शाहजहां ने करवाया था। इस किले में दिल्ली दरवाजा, अमरसिंह दरवाजा, दरियाई दरवाजा तथा दर्शनी दरवाजा नामक चार दरवाजे हैं। पर्यटकों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में अमर सिंह दरवाजा ही खुला होता है। किले के अंदर तीन मस्जिदें भी हैं – मीना मस्जिद, शाही मस्जिद और नगीना मस्जिद जो दर्शनीय है।

रामबाग: यह बाग अपनी हरियाली और सुंदरता से यहां आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बाबर द्वारा बनाए गए इस बाग के बारे में कहा जाता है कि यह भारत का पहला मुगल उद्यान था। इस बाग के सौंदर्य को पास बहती यमुना नदी और भी मनमोहक बना देती है।

प्यार की निशानी ताजमहल की ये 5 बातें आपको कर देंगी हैरान

ताजमहल, उसकी खूबसूरती और उससे

जुड़ी खूबसूरत यादों के बारे में सभी बातें

करते हैं। मगर इस धरोहर के बारे में

जितना सुनों उतना कम ही लगता है,

परंतु इसमें से कुछ हकीकत और कुछ

फसाना भी हैं। हम यहां आपको

ताजमहल से जुड़ी ऐसी 5 बातें बता रहे

हैं, जो संभवतः आप नहीं जानते होंगे-

आगरा में नहीं बनना था ताजमहल

ताजमहल का निर्माण आगरा में नहीं होने वाला था, मुमताज महल जिसके लिए ताजमहल बनवाया गया था, उनकी मौत दरअसल आगरा में हुई ही नहीं थी, उनकी मौत बुरहानपुर में हुआ था, जो आज के समय में मध्य प्रदेश में है। शाहजहां ने ताज महल के लिए बुरहानपुर में तामी नदी के ठीक किनारे एक जगह पसंद की थी, लेकिन बुरहानपुर में जरूरत के अनुसार सफेद मार्बल नहीं पहुंच सके, इसलिए बाद में ताजमहल आगरा में बनाने का फैसला किया गया। बुरहानपुर में तामी नदी के किनारे आज भी वह जगह विरान पड़ी है।



व्यक्ति से मारपीट के आरोप में शिवसेना की महिला पार्षद पर मामला दर्ज

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के पालघर जिले के नालासोपारा में एक सोशल मीडिया मंच पर की गई एक टिप्पणी को लेकर एक व्यक्ति से मारपीट के आरोप में शिवसेना की महिला पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से दर्ज कराई गई शिकायतों के बाद पीड़ित और दूसरे पक्ष के एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी हेमलता सिंह और अन्य प्रमुख फरार हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हेमलता सिंह वसई विरार शहर महानगर पालिका में पार्षद हैं। पुलिस के मुताबिक यह घटना विश्वकर्मा नामक व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद हुई। अपनी शिकायत में विश्वकर्मा ने कहा कि उन्हें अर्जुन दुबे नामक व्यक्ति ने एक हॉटल में बुलाया। जब विश्वकर्मा वहां पहुंचे तो पार्षद हेमलता ने अपने सहयोगी अमरीश के साथ उनसे कहासुनी हुई। आरोप है कि उन्होंने विश्वकर्मा को धक्का दिया, थप्पड़ मारे और मारपीट की। शिकायत में यह भी आरोप है कि मारपीट में पीड़ित की सोने की चेन छीन ली गई और मोबाइल फोन चोरी कर लिया। पुलिस ने घटना के सिलसिले में दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने विश्वकर्मा और पार्षद के सहयोगी मनीष सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।

टीएमसी रैली अनुमति पर कलकत्ता हाईकोर्ट में आज सुनवाई

कोलकाता (एजेंसी)। कोलकाता हाईकोर्ट 17 सितंबर को महत्वपूर्ण पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगा। यह याचिका पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर की गई है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस को हुगली जिले के श्रीरामपुर में निजी जमीन पर जनसभा आयोजित करने की अदालत की पिछली मंजूरी को चुनौती दी गई है। यह जनसभा मूल रूप से 11 सितंबर को होनी थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी। राज्य की सुप्रेम सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता बिचंदल भट्टाचार्य ने अदालत को सूचित किया कि मुख्य न्यायाधीश रवींद्र विठ्ठलराव घुगे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ की अनुमति से यह पुनर्विचार याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने घोषणा की है कि पुनर्विचार याचिका पर 17 सितंबर को सुनवाई होगी। सुप्रेम सरकार और निजी जमीन के मालिक ने खंडपीठ के समक्ष यह प्रश्न उठाया है कि क्या जनग्राथ ज्यू ट्रस्टी बोर्ड की जमीन पर कोई राजनीतिक रैली, आंदोलन या बैठक आयोजित की जा सकती है। इस मामले में, एक एकल पीठ ने श्रीरामपुर में भीड़-भाड़ वाले जैती रोड के बग़ाय उसी निजी जमीन पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जनसभा आयोजित करने की अनुमति दी थी। अब राज्य सरकार और निजी जमीन मालिक दोनों ने इस आदेश को चुनौती दी है, जिस पर अदालत की नजर है।

उत्तर प्रदेश में 15,012 शिक्षक पदों पर बंपर भर्ती शुरू, ओटीआर अनिवार्य

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने 15,012 शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, जिसकी घोषणा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने की है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) अनिवार्य होगा। यह भर्ती तब आई है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले छह महीनों में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है, जो मिशन रोजगार का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछले नौ वर्षों में 9.30 लाख से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी हैं। कुल 15,012 पदों में असिस्टेंट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी) शामिल हैं। इनमें माध्यमिक शिक्षा विभाग में असिस्टेंट टीचर (प्राइमरी से जुड़े) के 897 पद, बेसिक शिक्षा विभाग में असिस्टेंट टीचर (शहरी) के 11,508 पद और लेक्चरर फेडर (पीजीटी) के 2,607 पद पर भर्ती की जाएंगी। आयोग के चेयरमैन डॉ. प्रशांत कुमार ने 15 सितंबर को इन भर्तियों के विज्ञापन जारी किए।

बिहार में बाढ़ का कहर :50 लाख प्रभावित, शिवराज ने दिया हर संभव मदद का भरोसा

पटना(एजेंसी)। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दे दिया है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ स्थिति का जायजा लिया, जहां लगातार बारिश और नदियों के उफान से करीब 50 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने हाजीपुर सहित कई इलाकों का दौरा कर बताया कि पानी का स्तर 2016 की बाढ़ से भी ऊपर है। उन्होंने कहा कि केले और मकई जैसी फसलें 10 दिनों से अधिक समय तक पानी में डूबी रहने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। इसके अलावा, हजारों घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं और पशुधन को भी नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर वे स्वयं हालात का जायजा लेने आए हैं। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में राज्य के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और बिहार को हर संभव सहायता दी जाएगी।

लोगों ने मेरा साथ दिया तो याद रखिए आप जैसे गुंडों को यूपी से पलायन करना पड़ेगा

—सांसद चंद्रशेखर का आरोप— फार्म हाउस में मेरी हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया

नगीना, एजेंसी।

भीम आर्मी चीफ और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। पिछले साल जिस महिला ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था अब वह भारत लौट आई है। इसके बाद से ही सियासी विवाद बढ़ गया है। करीब 3 दिन पहले चंद्रशेखर आजाद और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के समर्थक आपस में भिड़ गए और धक्का-मुक्की तक मामला पहुंच गया। अब चंद्रशेखर ने एक्स पर खुलासा किया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रशेखर ने मंगलवार देर रात एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि एक फार्म हाउस में मेरी हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया है। मैं यह बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मेरे पास जो सूचनाएं और स्रोत हैं, वे गलत नहीं हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए और हत्या की साजिश से लेकर बाराबंकी



हिंसा में शामिल लोगों की भूमिका सामने लाई जाए। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं अपने विरोधियों से भी कहना चाहता हूं कि मौत तो एक दिन आनी है, मौत से डरकर जिया नहीं जा सकता। अगर मेरी मौत आपके जो सूचनाएं और स्रोत हैं, वे गलत नहीं हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए और हत्या की साजिश से लेकर बाराबंकी

जैसे गुंडों को उत्तर प्रदेश से पलायन करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि आज सवाल सिर्फ मेरी सुरक्षा का नहीं है। जब सुरक्षा प्राप्त एक चुने हुए जनप्रतिनिधि और सांसद के जिया नहीं जा सकता। अगर मेरी मौत आपके जो सूचनाएं और स्रोत हैं, वे गलत नहीं हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए और हत्या की साजिश से लेकर बाराबंकी

और न्याय की स्थिति क्या होगी.

भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। संघर्ष जारी रहेगा। मौत से डरकर जिया नहीं जा सकता। बता दें बाराबंकी में 3 दिन पहले चंद्रशेखर और उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड रोहिणी धावरी के समर्थक भिड़ गए थे। चंद्रशेखर लखनऊ से 1 हजार कार्यकर्ताओं के साथ गाँडा में कारोबारी विनोद साहनी हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने बैरिकेडिंग कर चंद्रशेखर को रोक दिया। इसी बीच रोहिणी धावरी के सैकड़ों समर्थक पहुंच गए। दोनों पक्षों में बहस हुई देखते ही देखते धक्का-मुक्की होने लगी। पुलिस ने किसी तरह रोहिणी के समर्थकों को हटया और चंद्रशेखर को पुलिस निरीक्षण भवन के पास ले गई। वहां सांसद सड़क पर बैठ गए। 20-25 मिनट बाद वे कार्यकर्ताओं के साथ लखनऊ लौट गए।

यूसीसी पर पवार गुट की प्रतिक्रिया: यह सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं

मुंबई, एजेंसी।

समान नागरिक सहिता (यूसीसी) को लेकर देश में जारी बहस के बीच, शरद पवार गुट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एन्सीपी (एसपी) नेता जितेंद्र आव्हाड ने मुद्दे पर टिप्पणी कर कहा कि कानूनी व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचना चाहिए और यूसीसी को केवल मुस्लिम समुदाय से जोड़कर देखा एक बड़ी गलतफहमी है।

नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि आदिवासी समुदायों, सिखों और पारसियों की अपनी अलग-अलग धार्मिक नीतियां और विधियां हैं। आव्हाड के अनुसार, इन सभी विविधताओं को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि विविधता ही देश की ताकत रही है। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान अनेकता में एकता से है।

यह प्रतिक्रिया तब आई है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में घोषणा की थी कि 2029 से पहले 21 एनडीए किया है, जिसे आव्हाड ने एक व्यापक शासित राज्य यूसीसी को लागू किया



जाएगा। वर्तमान में, केवल उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है, जबकि असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों की विधानसभाओं से यह पारित हो चुका है, लेकिन अभी तक इस कानून को अमल में नहीं लाया गया है। केंद्रीय मंत्री शाह के बयान के बाद एनडीए के भीतर भी मतभेद सामने आए हैं। बिहार में जेडीयू नेता श्याम रजक ने स्पष्ट किया है कि उनके राज्य में यूसीसी लागू नहीं होगा। वहीं, बीजेपी के सहयोगी चियाग पासवान और उमैद कुशवाहा ने भी सीधे तौर पर इसका समर्थन करने के बजाय देखो और इंतजार करो (वेट एंड वॉच) का रुख अपनाया है। दूसरी ओर, असदुद्दीन ओवैसी सहित कई मुस्लिम नेताओं ने यूसीसी का पुरजोर विरोध भी 2029 से पहले 21 एनडीए किया है, जिसे आव्हाड ने एक व्यापक शासित राज्य यूसीसी को लागू किया

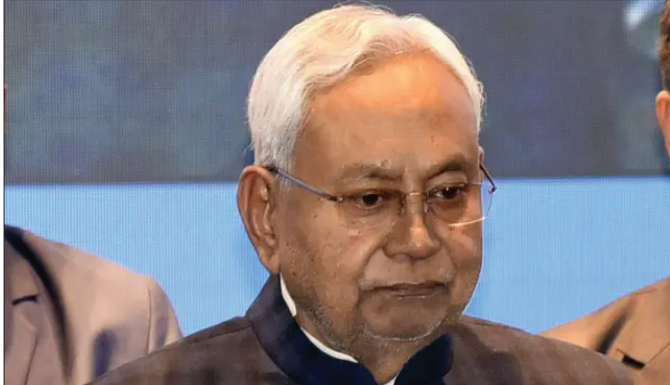
नीतीश कुमार ने 18 को बुलाई अहम बैठक, यूसीसी पर चर्चा होने की उम्मीद

—अमित शाह के यूसीसी के ऐलान के बाद बिहार में राजनीतिक सरगमी तेज

पटना, एजेंसी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) पर किए गए ऐलान के बाद बिहार में नई राजनीतिक सरगमी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने पार्टी के सांसदों, विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों की बैठक बुलाई है। यह बैठक 18 सितंबर को पटना में होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में यूसीसी पर चर्चा होने की उम्मीद है और एजेंडे में फरक्का जल संधि भी शामिल हो सकती है।

यह घटनाक्रम अमित शाह के उस बयान के कुछ दिनों बाद हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार वाले सभी 21 राज्यों में यूसीसी लागू किया जाएगा। इस घोषणा ने



नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। खासकर जेडीयू जैसे एनडीए सहयोगियों के बीच। यह बैठक इसलिए अहम है क्योंकि जेडीयू ने अब तक यूसीसी पर सावधानी भरा रुख अपनाया है। बिहार के डिट्टी सीएम

विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि पार्टी अपना रुख तय करने से पहले प्रस्तावित कानून की जांच करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी ने कहा कि पार्टी को अभी यूसीसी कानून की डिटेल्स के

बारे में जानकारी नहीं है और वह अपनी कोई भी चिंता केंद्रीय गृह मंत्री तक पहुंचाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में जटिलताओं को कोई वजह नहीं है। चौधरी ने कहा कि अगर हमें इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता है, तो हम बिना किसी वजह के इसका विरोध क्यों करेंगे? और अगर चिंता की कोई बात होगी, तो उसे केंद्रीय गृह मंत्री को बताया जाएगा।

जेडीयू के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट संजय कुमार झा ने संकेत दिया है कि पार्टी यूसीसी के मुद्दे पर अमित शाह से बातचीत करेगी। जेडीयू के 12 लोकसभा सांसद हैं, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का एक अहम हिस्सा है और बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है।

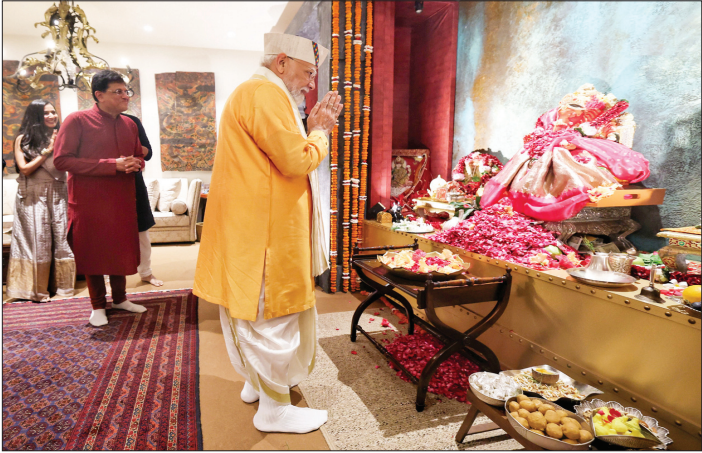
पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर बप्पा के दर्शन किए

गृह मंत्री अमित शाह ने भी टेका मत्था

नई दिल्ली, एजेंसी।

गणपति उत्सव के पावन अवसर पर देश के बड़े राजनेताओं ने श्रद्धा और उल्लास के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश के दर्शन किए और देशवासियों के लिए सुख-समृद्धि की कामना की। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नई दिल्ली स्थित आवास पहुंचे, जहां उन्होंने गणपति बप्पा के दर्शन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और आरती उतारी।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। उन्होंने धोती-कुर्ता और सिर पर महाराष्ट्र की पारंपरिक टोपी धारण कर रखी थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर इस विशेष क्षण की तस्वीरें साझा करते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और कामना की कि भगवान श्री गणेश सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री के अपने आवास पर आने पर आभार व्यक्त किया और इसे अपने परिवार के लिए सौभाग्य बताया। इसके अलावा, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी पीयूष गोयल के आवास पर पहुंचकर



गणपति बप्पा के दर्शन किए और शांति व समृद्धि की प्रार्थना की। दूसरी ओर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह पहुंचकर गणेश उत्सव में हिस्सा लिया। उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा के दर्शन किए और पूजा-अर्चना कर देशवासियों के कल्याण का आशीर्वाद मांगा। इसके पश्चात, गृह मंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर

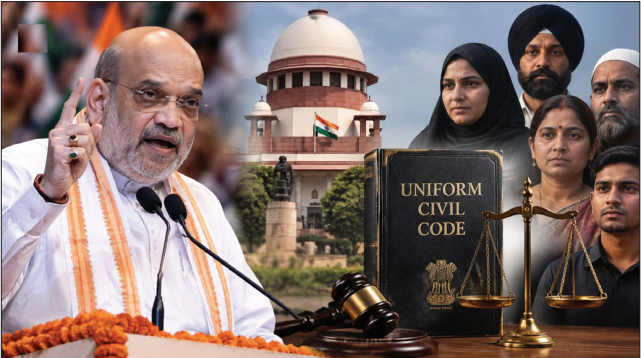
भी गए, जहां उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ बप्पा के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान राजनीतिक दिग्गजों के इन आयोजनों से देश भर में गणेश चतुर्थी का उल्लास और अधिक बढ़ गया। विभिन्न नेताओं के इन आयोजनों ने उत्सव के पारंपरिक और सांस्कृतिक महत्व को और प्रगाढ़ किया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं।

चार दशक पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अब यूसीसी की होगी दस्तक

नई दिल्ली, एजेंसी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर राजनीतिक सरगमी बढ़ा दी है। शाह ने कहा है कि भाजपा-एनडीए शासित 21 राज्यों में 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी कानून लागू कर दिया जाएगा। हालांकि, इस घोषणा के तुरंत बाद भाजपा की सहयोगी जेडीयू ने बिहार में यूसीसी लागू करने से इनकार कर दिया। शाह ने तीन तलाक खत्म करने का उदाहरण देते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिलें हैं और अब यूसीसी भी लागू होगा। यह मुद्दा नया नहीं है, दरअसल, सुप्रीम कोर्ट पिछले चार दशकों से भी अधिक समय

से यूसीसी की आवश्यकता पर जोर दे रहा है, लेकिन राजनीतिक नफा-नुकसान के चलते सरकारों ने इस पर खास ध्यान नहीं दिया। यूसीसी का अर्थ है देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे सिविल मामलों में धर्म-आधारित पर्सनल लॉ की जगह एक समान कानूनी व्यवस्था। इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 44 है, जो नीति-निर्देशक तत्वों में शामिल है, यानी इसे सीधे अदालत के जरिए लागू नहीं कराया जा सकता। कानून बनाना संसद या विधानसभाओं का काम है। बावजूद इसके, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकारों का ध्यान इस ओर खींचा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 1985 के



मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मामले में यूसीसी की जरूरत पर जोर दिया था। यह फैसला मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ता अधिकार से जुड़ा था और इसने यूसीसी को राष्ट्रीय

राजनीति में एक प्रमुख संवैधानिक मुद्दे के रूप में स्थापित किया। इसके बाद, 1995 के सरला मुद्दल बनाम भारत सरकार मामले में कोर्ट ने फिर सरकार को याद दिलाया कि विवाह और

उत्तराधिकार जैसे मामले धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के हैं और अनुच्छेद 44 पर 'फेश तरीके से फैसला' लेने को कहा। 2003 में जॉन वल्लभट्टम बनाम भारत सरकार और 2019 में जोस पाउलो कुट्टिहो बनाम मारिया लुइज वैलेंटिना पेरेड्रा मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने संसद को कॉमन सिविल कोड बनाने की दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया। हालिया सुनवाई में भी कोर्ट ने महिलाओं के समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए यूसीसी को एक प्रभावी रास्ता बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि इसे लागू करना विधायिका का ही काम है। सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के बार-बार कहने के बावजूद सरकारों ने इस पर कदम क्यों नहीं उठाए? इसकी मुख्य

वजहें राजनीतिक संवेदनशीलता, अल्पसंख्यक समुदायों की आशंकाएं और यूसीसी का असल स्वरूप तय करने की जटिलता रही हैं। पर्सनल लॉ में बदलाव धार्मिक पहचान और सामाजिक परंपराओं से जुड़ा होने के कारण हमेशा एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। सरकारों को डर रहा कि बिना पयोित बातचीत के इसे लागू करने पर धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा, विभिन्न धर्मों के नियमों को एक समान कानून में ढालना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। राजनीतिक सहमति का अभाव भी एक बड़ी बाधा रही है, जैसा कि अमित शाह के हालिया बयान पर जेडीयू का रुख दिखाता है।

आतंकियों के ठिकानों को तबाह करना जारी रखेगा इजरायल : नेतन्याहू

यरुशलम, एजेंसी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेजाकिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एक और बड़ी जीत हासिल की है और लेबनान के सुरक्षा क्षेत्र में मौजूद आतंकवादी दांचे को नष्ट करने का अभियान जारी रहेगा। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेतन्याहू के हवाले से कहा, 'हमने हिजबुल्लाह के खिलाफ एक और बड़ी जीत हासिल की है। हमने ब्यूफोर्ट रिज और अली अल-ताहरे रिज पर उसके प्रमुख आतंकवादी गढ़ों को नष्ट कर दिया है। हमारी नीति स्पष्ट है कि लेबनान के सुरक्षा क्षेत्र में मौजूद आतंकवादी दांचे को खत्म करना जारी रहेगा। इजरायल के लिए किसी भी खतरे को बढ़ाश्त नहीं किया जाएगा।' नेतन्याहू ने इजरायल के दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने अब भी सबक नहीं सीखा और दोबारा हमला करने का विकल्प चुना, तो उन्हें पहले से भी अधिक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अभी कुछ काम बाकी है और ईश्वर की मदद से उसे भी पूरा किया जाएगा। इस बीच, पिछले महीने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने कहा था कि इजरायल और लेबनान के बीच रोम में हुई ताजा वार्ता में सीमा विवाद और कैदियों की वापसी के मुद्दे पर सकारात्मक प्रगति हुई है। 7 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में आउन ने बताया था कि रोम वार्ता में चार प्रमुख मुद्दों- युद्धविराम, घरों को ढहाने की कार्रवाई, सीमा और कैदियों की वापसी तथा पायलट क्षेत्रों की पहचान पर चर्चा हुई। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि इन मुद्दों पर जल्द ही व्यावहारिक कदम सामने आएंगे।

केरल की ब्लॉगर अरुणिमा ने अफगानिस्तान में गिरफ्तारी का दावा किया

काबुल, एजेंसी। केरल की एक प्रसिद्ध महिला ट्वेल ब्लॉगर अरुणिमा ने सोमवार को दावा किया कि उन्हें अफगानिस्तान के बामियान में 'मुजाहिदीन' ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने भारतीय दूतावास से संपर्क करने के लिए मदद मांगी। अपनी फेसबुक पेज पर उन्होंने एक पोस्ट साझा की। इसमें स्थानीय अधिकारियों के एक कथित आधिकारिक संदेश का अनुवाद था, जिसके अनुसार उन्हें मुजाहिदीन ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अपडेट में कहा, 'मैं अफगानिस्तान में परेशानी में हूं। मैं बामियान में हूं।' पीटीआई इल पोस्ट की संख्यता की पुष्टि नहीं कर सका। विदेश मंत्रालय से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पोस्ट में गिरफ्तारी की परिस्थितियों या उन्हें हिरासत में लेने वालों के बारे में अधिक विवरण नहीं था।

लीबिया में फंसे 171 सोमाली प्रवासी घर लौटे

सोमाली , एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) की पहल पर एक विशेष चार्टर उड़ान के माध्यम से 171 सोमाली प्रवासियों को लीबिया से वापस घर भेजा गया। लीबिया में फंसे 171 सोमाली प्रवासियों में तीन नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। आईओएम ने बताया कि बेहतर जीवन की तलाश में प्रवासियों का ये समूह कई देशों से गुजरते हुए लीबिया पहुंचे थे। वहां मानव तस्करो के चंगुल में फंसेने के बाद इन्हें शोषण, दुर्व्यवहार और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। प्रवासियों की विशेष प्लाइट सबसे पहले उत्तरी सोमालिया के हरगेइसा में उतरी, जहां 42 प्रवासी उतरे। इसके बाद शेष यात्री राजधानी मोगादिशु पहुंचे, जहां अधिकारियों और उनके परिवजनों ने उनका स्वागत किया।

भारतीयों को अब उज्बेकिस्तान में 30 दिन तक वीजा-मुक्त प्रवेश

ताशकंद, एजेंसी। उज्बेकिस्तान में भारतीय दूतावास ने यात्रा संबंधी नई जानकारी साझा करते हुए कहा कि चुनिंदा देशों के वैध मल्टीपल-एंट्री वीजा रखने वाले भारतीय नागरिक उज्बेकिस्तान में 30 दिन तक बिना उज्बेक वीजा के रह सकते हैं। इसके लिए यात्रियों के पास संबंधित देशों का वैध बिजनेस या टूरिस्ट वीजा और अपने देश या किसी तीसरे देश का कम्पर्म रिटर्न या आगे की यात्रा का हवाई टिकट होना जरूरी है। दूतावास के अनुसार, यह सुविधा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, शेगेन समझौते वाले देशों, ब्रिटेन और अमेरिका के वैध मल्टीपल-एंट्री वीजा धारकों को मिलेगी।

होर्मुज के बाद सऊदी ने भी बंद की तेल की पाइपलाइन

रियाद, एजेंसी। मिडिल ईस्ट जारी संघर्ष का असर अब वैश्विक तेल बाजार पर बढ़ता दिख रहा है। सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट अर्थेल पाइपलाइन को ड्रोन हमले से हुए नुकसान के बाद अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया गया है। सऊदी अरब की यह पाइपलाइन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक रास्ता मानी जाती थी। इस पाइपलाइन के बंद होने से दुनिया की तेल सप्लाई को लेकर टेंशन बढ़ गई है।

मीडिया एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, अगर पाइपलाइन जल्द शुरू नहीं होती है तो वैश्विक तेल सप्लाई का करीब 4 फीसदी हिस्सा इससे प्रभावित हो सकता है।

सऊदी अरब की यह पाइपलाइन लगभग 1,200 किलोमीटर लंबी है। यह अगर प्रत्यक्षीय को पार करते हुए कच्चे तेल को लाल सागर के पास यानबू पोर्ट तक पहुंचाती है। दुनिया की 4 से 5 फीसदी तेल सप्लाई : स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के बाद इस पाइपलाइन से करीब 40 से 50 लाख बैरल तेल रोजाना भेजा जा रहा था, जो दुनिया भर की कुल तेल सप्लाई का करीब 4 से 5 फीसदी हिस्सा है। यह रूट इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जारी तनाव के कारण टैंकरों की आवाजाही लगभग ना के बराबर है। ऐसे में सऊदी अरब की यह पाइपलाइन एक अहम विकल्प बन



गई थी।

यानबू में सिर्फ 5 से 7 दिन का स्टॉक : पाइपलाइन बंद होने के बाद अब यानबू में रखे तेल के भंडार पर अतिरिक्त दबाव बन गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा स्टॉक के सहारे सऊदी अरब लगभग 5 से 7 दिन तक अपना निर्यात जारी रख

सकता है। मिस्त्र के एन सुखना और सिदी करीर बंदरगाहों पर मौजूद सऊदी अरब के अतिरिक्त भंडार से कुछ और समय तक मदद मिल सकती है, लेकिन यह स्थिति पाइपलाइन के लंबे समय तक बंद रहने की पूरी तरह भरपाई नहीं कर सकती। पाइपलाइन की मरम्मत में कितना समय लगेगा,

इस पर अभी अलग-अलग आकलन सामने आ रहे हैं। कुछ का कहना है कि इसमें कई सप्ताह लग सकते हैं, हालांकि यह संभावना भी जताई जा रही है कि सीमित मात्रा में पंपिंग अपेक्षाकृत जल्द दोबारा शुरू हो सकती है। सऊदी का तेल उत्पादन भी हुआ कम : पाइपलाइन से जुड़ा यह संकट ऐसे वक्त में सामने आया है, जब सऊदी अरब पहले से ही अपने तेल उत्पादन में बड़ी कटौती कर चुका है। रॉयटर्स के अनुसार, अगस्त में देश का कच्चे तेल का उत्पादन लगभग 62 लाख बैरल प्रतिदिन रहा, जो फरवरी में दर्ज 1.09 करोड़ बैरल प्रतिदिन के स्तर से काफी कम

है।उत्पादन में इस भारी गिरावट और निर्यात के वैकल्पिक मार्गों में आई रुकावट ने वैश्विक ऊर्जा बाजार की चिंताओं को और गहरा कर दिया है। इसके चलते ओपेक+ देशों की सप्लाई बढ़ाने की योजनाओं पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। रॉयटर्स के अनुसार, 14 सितंबर को ब्रेट क्रूड की कीमत बढ़कर लगभग 107.81 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई, जबकि अमेरिकी ड्रुड्रू करीब 102.94 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड हो रहा था। अगर पाइपलाइन जल्द बहाल नहीं होती और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तथा लाल सागर में भी तेल की सप्लाई बाधित रहती है।

ट्रंप को चुनौती देगा कनाडा?: अमेरिका से निवेश खींचने की तैयारी में कार्नी, समिट में जुटेंगे 300 दिग्गज सीईओ



ऊर्जा और जरूरी खनिजों के संसाधनों, वहां के पड़े-लिखे वर्कफोर्स और उन ट्रेड एग्रीमेंट्स की ओर इशारा किया, जिनकी वजह से कनाडा में मौजूद कंपनियों को दुनिया भर में लगभग 1.5 अरब ग्राहकों तक पहुंच मिलती है। कनाडा को भरोसा है कि वह ट्रंप का सामना कर सकता है और अपने निवेश के स्रोतों में विविधता ला सकता है। लेकिन यह शिखर सम्मेलन कनाडा के लिए एक नाजुक समय पर हो रहा है। व्यापार वार्ता 21 अगस्त को विफल हो गई, जिसके बाद ट्रंप ने लगभग 20 अरब अमेरिकी डॉलर के कनाडाई सामानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया। कनाडा ने जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद वाशिंगटन ने फिर

से दबाव बढ़ाते हुए कुछ कनाडाई आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की और बड़े, दीर्घकालिक अमेरिकी सरकारी अनुबंधों से कनाडाई उत्पादों को बाहर करने की दिशा में कदम उठाए। ट्रंप के टैरिफ और मैन्युफैक्चरिंग को बॉर्डर के दक्षिण में ले जाने की कोशिशें उस चीज को कमजोर कर रही हैं, जो लंबे समय से विदेशी निवेशकों के लिए देश के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक थी। कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड के तहत विशाल अमेरिकी बाजार तक भरोसेमंद पहुंच।

वित्त मंत्री फ्रांस्वा-फिलिप शैम्पेन ने क्या कहा : जब पूछा गया कि क्या कनाडा ट्रंप के साथ ट्रेड डील के बिना लंबे समय तक टिक सकता है, तो वित्त मंत्री फ्रांस्वा-फिलिप शैम्पेन ने कहा कि ओटावा प्रभावित व्यवसायों और कर्मचारियों की मदद करने के लिए तैयार है। शैम्पेन ने 'द एसोसिएटेड प्रेस' को बताया, 'हमारे पास अपने उद्योगों और कर्मचारियों की मदद करने के लिए जरूरी संसाधन हैं - चाहे कितना भी समय लगे या जो कुछ भी करना पड़े।' सरकार ने सोमवार को यह भी कहा कि वह 1 अरब अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक के निवेश के लिए कर संबंधी निर्णयों को प्राथमिकता देगी, जिससे बड़े निवेशकों को पूंजी लगाने से पहले अधिक निश्चितता

मिलेगी।

कनाडा पर दांव लगाने पर कार्नी ने क्या कहा: कार्नी वैश्विक निवेशकों से व्यापार युद्ध को नजरअंदाज करते हुए कनाडा पर दांव लगाने का आग्रह कर रहे हैं। साथ ही ट्रंप के नेतृत्व में तेजी से अप्रत्याशित होते जा रहे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कनाडा के कानून के शासन और विश्वसनीयता की तुलना स्पष्ट रूप से कर रहे हैं। कार्नी ने कहा, 'निवेशकों को एक ऐसा देश मिलेगा जो कानून के शासन का सम्मान करता है और एक ऐसा देश जो भरोसेमंद है। दुनिया में ऐसा संयोजन बहुत कम देखने में मिलता है। यह एक आकर्षक संयोजन है।'

इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक पूंजी को महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी, रक्षा, उन्नत विनिर्माण और ऊर्जा के क्षेत्र में प्रमुख परियोजनाओं के साथ जोड़ना है। सोमवार को एक बड़े निवेश की घोषणा की गई। बेल कनाडा ने कहा कि वह सरस्केचेवान में पहले से निर्माणाधीन एआई डेटा-सेंटर परियोजना को चार गुना बढ़ाएगी, जिससे 1.2 गीगावाट की सुविधा का मार्ग प्रशस्त होगा और कुल अनुमानित पूंजी निवेश 50 अरब कनाडाई डॉलर (36 अरब अमेरिकी डॉलर) से अधिक हो जाएगा।

ट्रंप को बड़ा झटका: मध्यावधि चुनाव से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति का बैन निरस्त

न्यूयॉर्क, एजेंसी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मेल मतपत्र प्रतिबंधों को फिलहाल खारिज कर दिया। इस निर्णय से राज्यों को अपनी पुरानी मेल मतपत्र प्रक्रियाओं को जारी रखने की अनुमति मिल गई है। यह फैसला मध्यावधि चुनावों में मतदान शुरू होने के बीच आया है। ट्रंप प्रशासन कांग्रेस पर नियंत्रण के लिए नवंबर के चुनावों से पहले इन प्रतिबंधों को लागू करना चाहता था।

डाक मतपत्र के मामले में जजों की राय क्या : जस्टिस सेमूअल एलियो कोर्ट और जस्टिस क्लेरेंस थॉमस ने इस संक्षिप्त आदेश का विरोध किया। जस्टिस ब्रेट कवानुश ने प्रतिबंधों को मध्यावधि चुनावों के लिए लागू न करने पर सहमति जताई। हालांकि, उन्होंने बाद में ट्रंप प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाने का संकेत दिया। यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि देश का लगभग एक तिहाई हिस्सा मेल द्वारा मतदान करता है।



2020 में मिली हार का कारण डाक मतपत्र को मानते हैं ट्रंप चुनाव अधिकारियों ने कहा कि मध्यावधि चुनावों से पहले पूर्ण बदलाव करना संभव नहीं था। अलाबामा, उत्तरी कैरोलिना और विस्कॉन्सिन ने पिछले सप्ताह ही मतदाताओं को मेल मतपत्र भेजना शुरू कर दिया था। उस समय भी नई प्रणाली सक्रिय नहीं थी। ट्रंप ने लंबे समय से मेल मतदान का विरोध किया है।

उन्होंने 2020 के चुनाव में जो बाइडेन से अपनी हार के लिए इसे गलत तरीके से दोषी ठहराया था। हालांकि, वह खुद अक्सर इसी तरीके से मतदान करते रहे हैं, जिसमें इस साल भी शामिल है। ट्रंप प्रशासन की क्या थी योजना : ट्रंप प्रशासन की योजना में राज्यों को एक समान लिफाफा शैली अपनानी थी। उद्योग मतदाताओं की सूची एक ऑनलाइन माध्यम पर जमा करनी होती। पोस्टल सर्विस उन राज्यों को मतपत्र देने से मना कर सकती थी जो नियमों का पालन नहीं करते। एक क्लिस्सलब्लोअर रिपोर्ट ने इस प्रणाली पर चिंता जताई थी। रिपोर्ट के अनुसार, ऑनलाइन माध्यम ठीक से नहीं बर्ता था। एक बार कोड त्रुटि से लाखों मेल मतपत्रों का पूरा समूह रद्द हो सकता था।

प्रतिबंधों को क्यों चुनौती दी गई : डेमोक्रेटिक राज्य अधिकारियों और मतदान अधिकार समूहों ने इन प्रतिबंधों

को अदालत में चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि राष्ट्रपति के पास चुनाव नियम तय करने का सांविधानिक अधिकार नहीं है। उनके अनुसार, ये नियम एक बड़े चुनाव के पूर्व संस्था पर मेल मतदान को लगभग समाप्त कर देंगे। निचली अदालतों ने ट्रंप की योजना को अवरुद्ध कर दिया था। इसमें राष्ट्रपति द्वारा नामित एक न्यायाधीश द्वारा जारी किया गया प्रारंभिक निषेधाज्ञा भी शामिल था। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ : ट्रंप प्रशासन ने निचली अदालतों के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। प्रशासन ने तर्क दिया कि पोस्टल सर्विस पर संघीय नियंत्रण उन्हें मेल मतपत्रों के लिए नियम तय करने की अनुमति देता है। उन्होंने यह भी कहा कि नियमों का पालन करना संभव था। संघीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्रारंभिक प्रक्रियात्मक निर्णय जीता था। हालांकि, जस्टिस ने योजना की वैधता पर स्पष्ट रूप से कोई फैसला नहीं सुनाया था।

भारत-बांग्लादेश रिश्तों में बदलाव की आहट, बांग्लादेश के मंत्री हुमायूं कबीर बोले- भारत संग नए अध्याय की जरूरत

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश ने भारत के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से आगे बढ़ाने की इच्छा जताई है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि ढाका अब पुराने आकर्षण से आगे बढ़कर भारत के साथ सीधे द्विपक्षीय संवाद के जरिए नया रिश्ता बनाना चाहता है।

बांलादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री ने भारत के साथ रिश्तों को लेकर अपनी सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल का दौर दोनों देशों के लिए असहज रहा है और अब संबंधों को नए आधार पर आगे बढ़ाने की जरूरत है।

भारत के साथ नए रिश्ते पर ढाका का जोर : विदेश मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हुमायूं कबीर ने कहा कि बांग्लादेश भारत को एक पड़ोसी और अन्य देशों की तरह एक देश के रूप में



देखता है। उनका कहना था कि अब ढाका भारत के साथ पुराने आकर्षण से आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ ऐसा नया रिश्ता बनाना चाहता है, जो सीधे द्विपक्षीय चर्चाओं और आपसी समझ पर आधारित हो। उनके मुताबिक, दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधी बातचीत ही संबंधों को आगे ले जाने का बेहतर रास्ता है।

बहुपक्षीय मंच नहीं, सीधी बातचीत पर जोर : हुमायूं कबीर ने कहा कि जिस देश के साथ बांग्लादेश बेहतर संबंध बनाना चाहता है, उसके साथ शुरुआती गंभीर बातचीत द्विपक्षीय यात्रा और सीधे संवाद के माध्यम से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान निर्धार पर होने वाली मुलाकात को दोनों देशों के रिश्तों की पहली बड़ी शुरुआत नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह टिप्पणी विशेष रूप से भारत के संदर्भ में है।

सीमा विवादों को राजनयिक तरीके से सुलझाने की बात : भारत-बांग्लादेश सीमा पर हाल की घटनाओं को लेकर पूछे गए सवालों पर हुमायूं कबीर ने कहा कि सरकार इन संवेदनशील मुद्दों को राजनयिक माध्यमों से उठाएगी।

झारखंड पुलिस जिसे मृत मान रही थी, वह विवाहिता सूरत से जिंदा मिली

सचिन GIDC पुलिस ने सुरक्षित खोज निकाला पिता ने दर्ज कराई थी हत्या की FIR

पति-ससुराल के प्रताड़ना से तंग आकर घर छोड़ा था

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

झारखंड और सूरत पुलिस को दौड़ाने वाला बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। किसी सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसी इस घटना में झारखंड के रांची जिले के खलारी पुलिस थाने में जिस विवाहिता की हत्या कर शव ठिकाने लगाने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, वही महिला सूरत के सचिन GIDC इलाके से जीवित मिल गई।

दरअसल, महिला की हत्या नहीं हुई थी। आरोप है कि पति और ससुराल पक्ष की कथित शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना से इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसे अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा था।

रोजाना के विवाद और कथित मारपीट से परेशान होकर वह बिना किसी को बताए करीब 10 दिन पहले झारखंड से सूरत आ गई थी।

पूरे मामले की शुरुआत झारखंड से हुई। 65 वर्षीय पिता छटु गोप ने खलारी पुलिस थाने में गंभीर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी 36 वर्षीय बेटी वीणी उर्फ वीणा देवी की शादी वर्ष 2010 में सामु महतो से हुई थी। दहेज देने के बावजूद पति कथित तौर पर वीणा के साथ लगातार मारपीट करता था। पिता ने आरोप लगाया कि 24 अगस्त 2026 को दामाद सामु महतो और अन्य लोगों ने मिलकर वीणा की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को कहीं छिपा दिया। कार्रवाई नहीं होने पर आखिरकार हत्या और सबूत मिटाने के आरोपों में मामला दर्ज किया गया।

मामले की असली तस्वीर जांच के दौरान कुछ और ही सामने



आई। महिला की हत्या नहीं हुई थी। वीणा देवी कथित तौर पर पति और ससुराल पक्ष की शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना से इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसे अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा था। रोजाना के विवाद और कथित मारपीट से परेशान होकर वह बिना किसी को बताए करीब 10 दिन पहले झारखंड से निकलकर सूरत आ गई थी। यहां उसने अकेले रहकर नई जिंदगी शुरू करने और कथित तौर पर ससुराल के माहौल से दूर रहने की कोशिश की।

मोबाइल लोकेशन ने खोला पूरे मामले का

राज उधर, खलारी पुलिस ने पिता की शिकायत के आधार पर हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को एक अहम सुराग मिला। तकनीकी सर्विलांस और मोबाइल नंबर की जांच करने पर पुलिस को पता चला कि जिस महिला को वह मृत मानकर उसका शव तलाश रही थी, उसका मोबाइल सूरत में सक्रिय था।

यह जानकारी मिलते ही झारखंड पुलिस भी हैरान रह गई और

उसने तत्काल सूरत की सचिन GIDC पुलिस से संपर्क किया।

सचिन GIDC पुलिस ने कुछ ही घंटों में महिला को खोज निकाला

झारखंड पुलिस से आधिकारिक जानकारी मिलने के बाद सचिन GIDC पुलिस तुरंत सक्रिय हुई। मोबाइल लोकेशन और मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। इसके बाद सचिन GIDC इलाके की शिवांजलि सोसायटी, राजूभाई की चाल में पुलिस ने दबिशा दी। वहां एक कमरे से पुलिस ने 36 वर्षीय वीणी देवी उर्फ वीणा देवी को पूरी तरह सुरक्षित हालत में बरामद कर लिया। वह वहां अकेली रह रही थी।

महिला को झारखंड पुलिस के हवाले किया गया

महिला के जिंदा मिलने के बाद पिता की हत्या की शिकायत के पीछे की पूरी कहानी भी सामने आ गई। सचिन GIDC पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद झारखंड पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए महिला को झारखंड पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। अब झारखंड पुलिस महिला का आधिकारिक बयान दर्ज करेगी और पति एवं ससुराल पक्ष पर लगाए गए प्रताड़ना के आरोपों की जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी।

सूरत पुलिस की 'नेत्रम' सिस्टम फेल ?

स्प्लेंडर से फरार हुआ सारोली अग्निकांड का आरोपी ANPR कैमरे बंद होने से नंबर प्लेट नहीं हो सकी ट्रेस

7 दिन से पुलिस के हाथ खाली

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सारोली की श्याम सिंगिनी टेक्सटाइल मार्केट में 17 दुकानों को आग के हवाले करने वाले आरोपी को पकड़ने में सूरत पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। घटना को एक सप्ताह बीतने के बावजूद पुलिस आरोपी तक नहीं पहुंच सकी है। CCTV फुटेज में आरोपी स्प्लेंडर बाइक पर फरार होता साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी के दावों के बीच वाहनों की नंबर प्लेट पढ़ने वाले हाईटेक ANPR कैमरों के बंद होने से पुलिस बाइक का नंबर तक हासिल नहीं कर पाई।

मंगलवार (9 सितंबर) की देर रात करीब साढ़े 12 बजे सिंगिनी मार्केट की छठी मंजिल पर 17 दुकानों में भीषण आग लग गई थी। इस घटना को आज एक सप्ताह पूरा हो गया है। आगजनी में 17 दुकानों के मालिकों को करीब 24 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है। आग के बाद मार्केट को अनिश्चितकाल के लिए सील कर दिया गया है। इसके चलते 200 से अधिक अन्य दुकानदारों के साथ वहां काम करने वाले कर्मचारी, टेंपो चालक और हमाल भी प्रभावित हुए हैं।

व्यापारियों का कहना है कि आग से हुए नुकसान की भरपाई बीमा से संभव हो सकती है, लेकिन मार्केट बंद होने से बेरोजगार हुए दुकानदारों और उनसे जुड़े लोगों की आर्थिक क्षति की भरपाई आसान नहीं है। मार्केट जल्द खुलवाने और आग लगाने वाले आरोपी को जल्द गिरफ्तार कराने के लिए व्यापारी पुलिस पर दबाव बनाने के साथ जांच में हरसंभव सहयोग का भरोसा भी दे रहे हैं। सारोली

पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की टीम भी आरोपी की तलाश में दिन-रात जुटी हुई है।

पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी के आने और आग लगाने के बाद भागने वाले दोनों रूट के कैमरे खंगाले हैं। CCTV में चेहरे पर सफेद कपड़ा बांधे एक शख्स बाइक पर भागता नजर आ रहा है। जांच के दौरान पुलिस ने यह भी पता लगाने की कोशिश की कि आरोपी आग लगाने से पहले किस दिशा से आया था और वारदात के बाद किस रास्ते से फरार हुआ। इसके अलावा करीब तीन घंटे तक सिंगिनी मार्केट परिसर में आरोपी की मौजूदगी के दौरान आसपास कितने मोबाइल फोन एक्टिव थे, इसका भी डेटा एनालिसिस किया गया है।

सूरत पुलिस की 'नेत्रम' सिस्टम पर सवाल दो महीने पहले शहर में आई बाढ़ के बाद सूरत पुलिस की 'तीसरी आंख' माने जाने वाले कई CCTV कैमरों के क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आई थी। आरोप है कि सिस्टम की खराब स्थिति और रखरखाव में लापरवाही के कारण खास तौर पर वाहनों की नंबर प्लेट पढ़ने वाले ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे भी बंद पड़े हैं।

सारोली अग्निकांड में आरोपी के चेहरे पर सफेद कपड़ा बांधकर स्प्लेंडर बाइक से फरार होने की बात CCTV फुटेज से सामने आई है। लेकिन यदि रास्ते में लगे ANPR कैमरे काम कर रहे होते, तो बाइक की नंबर प्लेट से उसके मालिक तक पहुंचने में पुलिस को मदद मिल सकती थी। अब बड़ा सवाल यह है कि स्मार्ट सिटी और हाईटेक निगरानी व्यवस्था के दावों के बीच ANPR कैमरे बंद क्यों पड़े हैं।

सायरन बजाकर सरकारी गाड़ी से महाराष्ट्र पहुंचे सूरत के डिप्टी मेयर

सुधाकर चौधरी बोले- मेयर और फायर विभाग को लिखित में दी थी जानकारी, किलोमीटर के चार्ज भी चुकाता हूं

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत के डिप्टी मेयर सुधाकर चौधरी एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। हाल ही में वे अपनी सरकारी गाड़ी लेकर महाराष्ट्र के शाहपुर गांव पहुंचे। खास बात यह रही कि सड़क पर ट्रैफिक नहीं होने के बावजूद सरकारी वाहन में तेज सायरन बजाते हुए गांव में प्रवेश किया गया। इस दौरान उनकी एंटी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद सरकारी वाहन के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठने लगे।

महाराष्ट्र तक सरकारी वाहन ले जाने का मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर नागरिकों और विपक्षी लोगों ने डिप्टी मेयर सुधाकर चौधरी की आलोचना शुरू कर दी। सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाली सरकारी गाड़ियों और उनके सायरन का इस्तेमाल निजी या धार्मिक यात्राओं के लिए किया जा सकता है ?

विवाद बढ़ने और लगातार हो रही आलोचनाओं के बीच डिप्टी मेयर सुधाकर चौधरी ने खुद सामने आकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया और

पूरे मामले में अपना पक्ष रखा।

अपने पक्ष में वीडियो जारी करते हुए सुधाकर चौधरी ने एक सरकारी पत्र भी सार्वजनिक किया। उनके मुताबिक, निजी कारणों से बाहर जाने के लिए उन्होंने 12 और 13 सितंबर के दौरान महानगरपालिका द्वारा आवंटित सरकारी वाहन को शहर से बाहर ले जाने की पूर्व अनुमति ली थी।

चौधरी ने दावा किया कि इस यात्रा के संबंध में उन्होंने पहले ही मेयर और फायर विभाग को लिखित रूप से जानकारी दे दी थी। उनका कहना है कि जब वाहन के बाहर ले जाने की जानकारी और अनुमति पहले से दी गई थी, तो गड़बड़ी के आरोप निराधार हैं।

कुलस्वामी के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने महाराष्ट्र गए थे चौधरी विवाद पर सफाई देते हुए डिप्टी मेयर सुधाकर चौधरी ने वीडियो में कहा कि वे किसी गैरकानूनी गतिविधि के लिए महाराष्ट्र नहीं गए थे, बल्कि धार्मिक कार्यक्रम और अपने कुलस्वामी के आयोजन में शामिल होने के लिए गए थे। उन्होंने बताया कि वे 12 सितंबर की सुबह सूरत से रवाना हुए थे और सभी धार्मिक कार्यक्रम पूरे करने के बाद 13 सितंबर की सुबह करीब 4 बजे सुरक्षित सूरत लौट आए थे।

चौधरी का कहना है कि यात्रा के दौरान सरकारी वाहन के इस्तेमाल से जुड़े नियमों का पूरा ध्यान रखा गया।

अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज करते हुए सुधाकर चौधरी ने मीडिया के प्रति नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि सरकारी वाहन के इस्तेमाल के किलोमीटर के हिसाब से जो भी चार्ज बनता है, उसका बिल हर महीने मिलता है और वे नियमित रूप से उसका भुगतान करते हैं।

चौधरी ने कहा कि बिना किसी पूर्व जांच के इस तरह की खबरें चलाना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल से संबंधित आधिकारिक बिल सार्वजनिक किया जाएगा, ताकि पूरे मामले की वास्तविकता लोगों के सामने आ सके।

अब पूरे मामले में मुख्य सवाल सरकारी वाहन को शहर से बाहर ले जाने की अनुमति और उसके इस्तेमाल से जुड़े नियमों को लेकर है। डिप्टी मेयर की ओर से अनुमति और किलोमीटर चार्ज का भुगतान किए जाने का दावा किया गया है, जबकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद सरकारी वाहन में सायरन के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठे हैं।

सूरत में विवाहित प्रेमी युगल का सामूहिक आत्महत्या

सिद्धनाथ महादेव मंदिर के पास तापी किनारे बैठकर

दोनों ने निगली जहरीली दवा,पहले प्रेमी फिर प्रेमिका की मौत

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत शहर में एक और सामूहिक आत्महत्या का हृदयविदारक मामला सामने आया है। वराछा इलाके में रहने वाली 29 वर्षीय विवाहित महिला और उतरण निवासी 40 वर्षीय विवाहित युवक ने वरियाव ब्रिज के नीचे सिद्धनाथ महादेव मंदिर के पास तापी नदी के किनारे बैठकर जहरीली दवा निगल ली।

दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के

दौरान पहले प्रेमी की मौत हो गई।

इसके बाद प्रेमिका ने भी कुछ ही समय के उपचार के बाद दम तोड़ दिया। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि दोनों के बीच चल रहे प्रेम संबंध में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ था, जिसके बाद दोनों ने यह आत्मघाती कदम उठाया। घटना के बाद दोनों परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई।

मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली और फिलहाल सूरत के वराछा में लाभेश्वर भवन के पास रहने वाली 29 वर्षीय खुशबू (बदला हुआ नाम) मंगलवार सुबह रोज की

तरह सफाई का काम करने के लिए घर से निकली थी।

शाम तक घर नहीं लौटने पर चिंतित पति ने उसके मोबाइल पर फोन किया। फोन किसी अज्ञात व्यक्ति ने उठाया और बताया कि एक महिला और एक युवक वरियाव ब्रिज के नीचे सिद्धनाथ महादेव मंदिर के पास बेहोशी की हालत में पड़े हैं। जानकारी मिलते ही परिजन तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और 108 एंबुलेंस के जरिए दोनों को स्मीमेर अस्पताल ले जाया गया। वहां इयूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने युवक की जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

प्रोसेसर्स की रेट वृद्धि पर FOSTTA और SGTPA की महत्वपूर्ण बैठक

सोमवार को SGTPA सदस्यों की विशेष बैठक

आपसी समन्वय से समाधान निकालने पर जोर

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत,प्रोसेसर्स द्वारा की गई रेट वृद्धि को लेकर शनिवार को फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन (FOSTTA) एवं साउथ गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसर्स एसोसिएशन

(SGTPA) के पदाधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में FOSTTA की ओर से अध्यक्ष हंसराज जैन, महामंत्री दिनेश कटारिया, संगठन महामंत्री गिरीश मिश्र, डायरेक्टर सुरेश मोदी, महेंद्र भायल एवं मुकेश केवलानी उपस्थित रहे। वहीं स्तंभक की ओर से अध्यक्ष जीतू वखारिया, कमल तुलसियान एवं मितुल मेहता शामिल हुए।

बैठक में FOSTTA ने



व्यापारियों से प्राप्त रेट वृद्धि संबंधी शिकायतों, सुझावों और चिंताओं को SGTPA के समक्ष रखा। दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों ने मौजूदा व्यापारिक परिस्थितियों और टेक्सटाइल व्यापार के विभिन्न घटकों के बीच सामंजस्य को लेकर विस्तार से चर्चा की।

SGTPA पदाधिकारियों ने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए निर्णय लिया कि सोमवार को

SGTPA अपने सदस्यों की विशेष बैठक आयोजित करेगा। इसमें FOSTTA द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक के बाद दोनों संगठनों के बीच आपसी समन्वय के माध्यम से उचित समाधान निकालने और व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए सामंजस्य स्थापित करने पर जोर दिया गया।

MLA संगीता पाटिल फोटोसेशन के लिए दो बार खेलकर चली गई'

CM के लोकार्पण वाला 10.81 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 14 महीने बाद भी धूल फांक रहा

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत के लिंबायत जोन में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10.81 करोड़ की लागत से बनाया गया अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लोकार्पण के करीब 4 महीने बाद भी पूरी तरह शुरू नहीं हो सका है। करोड़ों रुपये खर्च कर तैयार किए गए इस मल्टीपर्पज हॉल में आधुनिक खेल सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन पर्याप्त कोच और उचित व्यवस्था के अभाव में अधिकांश खेल गतिविधियां ठप पड़ी हैं।

सूरत महानगरपालिका ने नवागाम में TP-41 (डिंडोली), फाइनल प्लॉट नंबर 101 पर यह अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया था। इसका भव्य लोकार्पण पिछले जुलाई में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों किया गया था। हालांकि, लोकार्पण के करीब 14 महीने बाद भी यह कॉम्प्लेक्स स्थानीय खिलाड़ियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं बन पाया है।

कॉम्प्लेक्स में टेबल टेनिस,

बैडमिंटन, जिम, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, खो-खो, कबड्डी, जूडो-कराटे और योग सहित विभिन्न इंडोर खेलों के लिए आधुनिक सुविधाएं तैयार की गई हैं।

लेकिन खेलों के लिए जरूरी प्रशिक्षकों और कोच की नियुक्ति नहीं होने के कारण अधिकांश गतिविधियां शुरू नहीं हो पाई हैं। महानगरपालिका ने करीब दो महीने पहले सभी खेलों के लिए मात्र 10 हजार मासिक मानदेय पर कोच रखने का प्रस्ताव किया था। आरोप है कि इतनी कम राशि में योग्य और अनुभवी कोच उपलब्ध नहीं हो रहे हैं।

बताया गया कि जो कोच उपलब्ध होने को तैयार हैं, वे सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में काम करने के बजाय केवल एक शिफ्ट में काम करने की मांग कर रहे हैं। इसके चलते फिलहाल सिर्फ योग की गतिविधि संचालित हो रही है, जिसमें करीब 80 लोग जुड़े हुए हैं।

दूसरी ओर, लाखों रुपये के आधुनिक खेल उपकरण इस्तेमाल के इंतजार में पड़े हैं। कुछ उपकरणों पर अब भी वही

प्लास्टिक कवर लगे हुए हैं, जो उन्हें नया लाए जाने के समय लगाए गए थे। इससे सवाल उठ रहा है कि क्या इन उपकरणों का अब तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ ?

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कर्मचारी दीपक राठौड़ के मुताबिक, सुबह टेबल टेनिस खेलने दो लोग और बैडमिंटन खेलने चार लोग आते हैं। यानी फिलहाल सिर्फ छह लोग इन खेल सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि जिम के लिए अभी कोई कोच नहीं है। कोच नियुक्त करने के लिए दो-तीन बार उच्च अधिकारियों के समक्ष मांग रखी गई और 10 हजार के मानदेय पर भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी किया गया, लेकिन अब तक कोच नहीं मिला है। इसलिए जिम भी शुरू नहीं किया गया है।

राठौड़ के मुताबिक, स्थानीय विधायक दो-तीन बार कॉम्प्लेक्स का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने इसे जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए थे।

सस रू संगीता पाटिल का दावा—कोच और फीस कम करने की मांग रखी

विधायक संगीता पाटिल ने कहा कि उन्होंने सूरत महानगरपालिका में कोच नियुक्त करने के लिए प्रतिनिधित्व किया है। साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की निर्धारित फीस कम करने की मांग भी रखी है।

कॉम्प्लेक्स शुरू होने से पहले ही बारिश के दौरान यहां करीब डेढ़ फीट पानी भर गया था। इसके कारण बास्केटबॉल कोर्ट की फ्लोरिंग खराब होने की बात सामने आई और उसे तत्काल हटाने की नौबत आ गई।

कॉम्प्लेक्स के संचालन के लिए महानगरपालिका ने 4 से 5 कर्मचारियों का स्टाफ भी तैनात किया है। ऐसे में जब कॉम्प्लेक्स से आय लगभग शून्य है, तब कर्मचारियों के वेतन के साथ भारी बिजली बिल का खर्च भी महानगरपालिका की तिजोरी पर पड़ रहा है।

कॉम्प्लेक्स नंदनवन टाउनशिप के पीछे रेलवे ट्रैक के पास अपेक्षाकृत एकांत स्थान पर स्थित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम के समय सुरक्षा को लेकर महिलाएं और युवतियां यहां आने में झिझकती हैं।

इसके अलावा महानगरपालिका